www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 28 | गोरखपुर, 19 जनवरी 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

मुस्लिम पति को भी कानूनन तलाक योग्यने का हक

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने गत दिनों एक फैसला सुनाया जो भारत में मुस्लिमों में तलाक से जुड़े कानूनों-प्रावधानों पर खास असर डालेगा। फैसला यह है कि-एक मुस्लिम पति अगर अपनी शादी खत्म करना चाहता है तो उसे इसके लिए पारिवारिक अदालत में याचिका दायर करने का हक है। अन्य शब्दावली में-उसे पारंपरिक मुस्लिम रिवाज के मुताबिक, गैरकानूनी ढंग से तलाक देने की जरूरत नहीं है। इस अदालती फैसले को कारगरता को तीन कानूनों की रोशनी में देखा जाना है- मुस्लिम विवाह अधिनियम-1939, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 और परिवार-न्यायालय अधिनियम-1984/ मुस्लिम रिवाज या कानून के मुताबिक देखें तो शादी की न्याय संगत समाप्ति तलाक (पति द्वारा तलाक), खुला (पत्नी द्वारा तलाक) या मुबारत (आपसी सहमति से तलाक) के रूप में हो सकती है।

स्मरणीय है कि- भारत में मुस्लिम तलाक कानून में अब तक दो बार सुधार किया जा चुका है। मुस्लिम महिलाओं के न्यायिक तलाक के अधिकार को मान्यता देने के लिए मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम-1939 बनाया गया था। वैसे पुरुषों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया था और न कोई किसी न्यायिक दखल के बिना तीन तलाक ही एकमात्र विकल्प बना रहा। चूंकि इस संबंध में मुस्लिम नियमों का समाज में भयंकर दुरुपयोग हो रहा था। इसलिए कुछ विद्वानों-न्यायाधीशों ने अपने फैसलों में गहरी चिंता जताई थी। इनसे उत्साहित होकर विवाहित लड़कियों के एक समूह ने राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके चलते-2017 के शायरा बानों मामले में संविधान पीठ के फैसले ने तलाक - उल- बिअदत की प्रथा को खारिज कर दिया। इस प्रथा या रिवाज के तहत पहले एक तरफा ढंग से तीन तलाक हो जाता था। अदालत की सिफारिश पा ही सरकार ने कानून बनाया- मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- 2019 और तलाक-उल-बिआदत को (अमान्य व अपराध करार दिया। वर्ष 1984 का पारिवारिक न्यायालय अधिनियम मूलतः पारिवारिक को सुलझाने के लिए बनाया गया था। यहां सुनवाई के लिए आने बाले मामलों में विवाह को शून्यता वैवाहिक हक की बहाली, कानूनन अलगाव और शादी का टूटना इत्यादि विषय शामिल हैं।

जानकारों की माने, गवालियर के इस मामले में एक मुस्लिम पतिने अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाते हुए पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। अदालत ने मुकदमें को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत वह उनके मामले पर विचार कर सके और फैसला सुना सके। इस फैसले के खिलाफ उस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय को ग्वालियर खंड पीठ में अपील की। अपील को खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ मंजूर कर लिया कि यद्यपि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 तलाक के इच्छुक पुरुषों के लिए कोई प्रावधान नहीं करता, फिर भी वे परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा-7 के तलाक की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। पीठ ने कहा, यह प्रावधान, जाति और समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करता। और अपनी प्रकृति में सर्व व्यापी है। यहां तक कि संवैधानिक नैतिकता सांविधानिक नैतिकता और भावना यह कहती है कि- किसी भी व्यक्ति को बिना उपचार या समाधान के बिया नहीं रखा जा सकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि एक मुस्लिम पुरुष को अपनी शिकायतों को जाहिर करने के लिए न्याय या न्यायिक मंच तक पहुंचने से वंचित नहीं किया जा सकता । ताजा अदालती फैसले के पीछे को चिंता और बुद्धिमत्ता को सराहिए।

अवकाश सूचना

प्रिय पाठकों, संवाददाताओं एवं स्वतंत्र लेखकों !

राष्ट्रीय पर्व 76 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 'घूंघट की बगावत' हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र कार्यालय में 26 जनवरी, 2025 को अवकाश रहेगा। अगला अंक 02 फरवरी, 2025 को प्रकाशित होगा। - व्यवस्थापक

ट्रंप के सामने वही चुनौतियां जो बाइडेन के सामने

यह विडंबना ही है कि आज अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट-स नेताओं में इस कदर दूरी बन गई है कि मुल्क में आम राजनीतिक सहमति नहीं बन पा रही है। वे दिन लद गये जब दोनों पार्टियां राष्ट्रहित में एक साथ आ जाती थी। लेकिन आज मसला जलवायु संरक्षण का हो या फिर ग्लोबल वार्निंग का, ए आई या फिर चीन से मुकाबला दोनों दल एक-दूसरे के सामने जंग की मुद्रा में है। जो बाइडेन आंतरिक रूप से विभाजित इस अमेरिका को एक करने में विफल रहे। देखना यह है कि बतौर नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुध्रुवीय और परस्पर निर्भर दुनिया में अमेरिका को प्रभावी नेतृत्व दिलाने में कितना सफल हो पाते हैं।

अमेरिका बेशक दूसरे देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण को लेकर उत्सुक रहा है, लेकिन बाडेन के कार्यकाल में उसे अपने ही घर में इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका को छाया अफगानिस्तान से सैनिकों को वापसी से भी प्रभावित हुई। अगस्त 2021 में करीब दो दशक पुरानी जंग का अंत करते हुए बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। हालांकि, इसके बारे में दोहा समझौता 2020 में ट्रंप के पिछले कार्य काल में ही हो गया था। लेकिन उनको विदाई के जो वीडियो आए या जिस तरह से उन्होंने वहां अपने टैंक और हथियार छोड़े, उससे विश्व बिरादरी में यही संदेश गया कि अमेरिका को वहां से सामना पड़ा है। यूक्रेन युद्ध को रोक पाना बाइडन की विफलता माना जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन को पैसे दिए, हथियार दिए, और सहायता भी दी। बावजूद इस-के तीन साल से यह जंग जारी है। इसने नाटो देशों तक में मतभेद पैदा कर दिया हो, इस युद्ध के बहाने रूस को कुछ हद तक कमजोर कर पाने में सफलता बाइडेन को मिली है।

पर प्रतिबंधों के बावजूद जिस तरह से मास्को अपनी अर्थव्यवस्था चलाता रहा उससे वॉशिंगटन को बहुत फायदा नहीं मिला सका। यहां तक कि परमाणु युद्ध की आशंका भी बनती-बिगड़ती रही है।

अपने विदाई भाषण में निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडेन ने अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट बढ़ती असहिष्णुता और समाप्त हो चुकी

राजनीतिक सहमति की तरफ इशारा किया है। उस-के गहरे निहितार्थ लगाए जा सकते हैं। दरअसल वह यह बताना चाह रहे थे कि जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद पर अमेरिका की नींव पड़ी है उसे खोखला किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कहते हुए वह अपनी परोक्षरूप में विफलता ही गिना रहे थे।

सवाल तो यही है कि-अपने चार साल के कार्य काल में वह अमेरिकी मूल्यों को बनाए रखने में इस कदर विफल क्यों रही वास्तव में बाइडेन के लिए चुनौती नवंबर, 2020 में तब शुरू हुई जब उन्हें राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। जनादेश को न मानते हुए रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी, 2021 को अपने समर्थकों के साथ कैपिटल हिल (संसद भवन) पर चढ़ाई कर दी थी। इस घटना के बाद सबक लेकर यदि बाइडेन ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में आम राय बनाने की कोशिश की होती तो शायद आज की तस्वीर अलग होती। मगर वह ऐसा करने में विफल रहे जिसकी वजह से अपने पूरे कार्य काल में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उन्हें पार्टी में भी विरोध का सामना करना पड़ा जिसकी झलक पिछले राष्ट्रपति-चुनाव में देखने को मिली। बाइडेन को न चाहते हुए भी अपनी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तक छोड़नी पड़ी और कमला हैरिस का नाम आगे करना पड़ा।

कुछ यही स्थिति पश्चिम एशिया की रही। उनके पूरे कार्य काल में यहां उथल-पुथल बनी रही। वास्तव में इस क्षेत्र को लेकर बाइडेन सरकार की कोई खास नीति रही ही नहीं जिस कारण स्थानीय खिलाड़ियों को अपना घेरा मजबूत करने में सफलता मिली। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने इसका अपने हित में फायदा उठाया यहां ईरान की ताकतों के खिलाफ विशेष नीति को दरकार थी, पर बाइडेन खामोश बने रहे।

परिणामतः ईरान और चीन में नजदीकियां बढ़ने लगी। ट्रंप बतौर राष्ट्रपति कभी-कभी सख्त नीति अपना लिया करते थे लेकिन बाइडेन ने बिल्कुल शांत रहना ही उचित समझा।

चीन को लेकर बाइडेन ने ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाया। ट्रंप ने क्वाड (भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका का संगठन) को सांगठनिक रूप देने का प्रयास किया था और बाइडेन ने इसकी ऑन लाइन बैठक आयोजित करके इस संगठन को शासनाध्यायों के स्तर तक सक्रिय कर दिया। यह उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी सामरिक सहमति बनाने में बाइडेन कुछ हद तक सफल रहे बेशक उन्होंने चीन से सीधे-सीधे मोर्चा नहीं लिया पर एक तरह से यह संदेश देने से भी नहीं चूके कि-हिंद महासागर पर किसी एक का दबदबा नहीं हो सकता इसका असर भी पड़ा। चीन दबाव में आया और नई दिल्ली के साथ उसने समझौता (सीमा समझौता) किया है, तो इसको एक बड़ी वजह भारत अमेरिका दोस्ती है। जिसे वह अपने फिर बड़ी चुनौती मानता है।

यही वह मुकाम है जहां हम यह कह सकते हैं कि बाइडेन के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार आया है। अव्वल तो हमने चीन पर काफी हद तक दबाव बनाए रखा फिर तमाम प्रतिबंधो के बावजूद हमने उस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बनाये रखे। जिसका वॉशिंगटन में कभी विरोध नहीं किया। यहां तक कि बाइडेन ने जाते-जाते भी एक अच्छी खबर हमारे लिए दी कि-अमेरिका अब हमारे परमाणु संस्थानों पर से प्रतिबंध हटाने की कवायद शुरू करने जा रहा है।

वैसे बाइडेन का कार्यकाल इसलिए भी याद रखा जायेगा कि उन्होंने सेना का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा शायद इसी लिए कि वह अमेरिका की छवि और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर ज्यादा सं-जीदा रहे हैं। अपने विदाई भाषण में उन्होंने यह चेतावनी दी है कि - अमेरिका में सत्ता पर अपना प्रभाव डालने वाला एक ओलिगाकी (कुलीनतंत्र) आकार ले रहा है। जिसकी कमान दौलतमंद के हाथों में है। उन्होंने फर्जी खबरों के प्रसार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को भी अमेरिकी लोकतंत्र के सामने संभावित खतरा बताया है। बाइडेन के अनुसार- टेक-इंडस्ट्रियल कांपलेक्स है यानी आज के अमेरिका में तकनीक व उद्योग से जुड़े लोग सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं पर हावी हो गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, जो लोग आजीविका की तलाश में स्थानीय और क्षेत्रीय सीमाओं के पार जाते हैं, उन्हें अपने मेजबान समाज में स्थायी रूप से बाहरी समझे जाने का अपमान सहना पड़ता है। श्रमिकों को अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर दुखद घटनाओं के पात्र के रूप में दिखाया जाता है, जिससे उनके योगदान और उन्हें प्राप्त मान्यता के बीच का अंतर उजागर होता है। राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के पीछे की ताकत होने के बावजूद, राष्ट्रीय महानता के विमर्श में उनकी भूमिका को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है। पॉलिसी शून्य होने के कारण अक्सर असुरक्षित छोड़ दिया जाता है यद्यपि प्रवासी कार्यबल राष्ट्रीय गौरव के प्रत्यक्ष चिह्नों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, फिर भी उनके अधिकारों को नियंत्रित करने वाली नीतियों का घोर अभाव है।

आखिर प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा का कारण क्या है?

भारत के असंगठित कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण लेकिन कमजोर वर्ग, प्रवासी श्रमिक, अक्सर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से बाहर रह जाते हैं। दशकों से कानूनी ढाँचे और सि-फारिशों के बावजूद, सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुँच अपर्याप्त रही है। अंतरराज्यीय प्र-वासी कामगार अधिनियम, 1979 में प्रावधान और असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (2007) और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2008) द्वारा श्रमिक पं-जीकरण के लिए सिफारिशों के बावजूद, ई-श्रम पोर्टल तक प्रवासी श्रमिक आधिकारिक डेटाबेस में काफी हद तक अदृश्य रहे। जबकि ई-श्रम पोर्टल पर 300 मिलियन से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, उनमें से अधिकांश को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एकीकृत नहीं किया गया है। मौसमी और परिपत्र प्रवासियों को वंचितता, कलंक, तस्करी और सार्वजनिक सेवाओं तक खराब पहुँच सहित अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी उच्च गतिशीलता सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को जटिल बनाती है। कई श्रमिकों में डिजिटल साक्षरता या ई-श्रम पंजीकरण और लाभ ट्रैकिंग के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुँच की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। राज्यों में अक्सर कल्याणकारी योजनाओं का असंगत कार्यान्वयन होता है, जिससे समन्वय सम्बंधी समस्याएँ पैदा होती हैं जो लाभों की पोर्टेबिलिटी को कमजोर करती हैं।

मौजूदा कल्याणकारी योजनाएँ जैसे कि मनरेगा, पीएम श्रम योगी मानधन और वन नेशन वन राशन कार्ड अक्सर अलग-अलग तरीके से काम करती हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों के लिए निर्बाध पहुँच में बाधाएँ पैदा होती हैं। 2021 में लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। इसमें 300 मिलियन से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें प्रवासियों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात शामिल है। यह कल्याणकारी योजनाओं के लिए श्रमिकों की बेहतर पहचान और लक्ष्यीकरण की सुविधा प्रदान करता है। हालाँकि, यह मुख्य रूप से एक रपंजीकरण अभियानर है जिसका सामाजिक सुरक्षा में समावेश पर सीमित ध्यान है। 2024 में लॉन्च किया गया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत करके पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। इसके लाभों में एकीकृत दृष्टिकोण, लाभों की पोर्टेबिलिटी और पारदर्शी तथा श्रमिक-अनुकूल प्रक्रिया शामिल है। हालाँकि, चिंताओं में मौजूदा योजनाओं का सीमित कवरेज, श्रमिकों में जागरूकता की कमी और अंतर-राज्य समन्वय का कमजोर होना शामिल है। ई-श्रम पोर्टल और ओएसएस प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों को सम्बोधित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, उनकी सफलता कार्यान्वयन बाधाओं पर काबू पाने, निर्बाध अंतर-राज्य समन्वय सुनिश्चित करने और श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर निर्भर करती है।

आंकड़ों के अनुसार, जो लोग आजीविका की तलाश में स्थानीय और क्षेत्रीय सीमाओं के पार जाते हैं, उन्हें अपने मेजबान समाज में स्थायी रूप से बाहरी समझे जाने का अपमान सहना पड़ता है। श्रमिकों को अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर दुखद घटनाओं के पात्र के रूप में दिखाया जाता है, जिससे उनके योगदान और उन्हें प्राप्त मान्यता के बीच का अंतर उजागर होता है। राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के पीछे की ताकत होने के बावजूद, राष्ट्रीय महानता के विमर्श में उनकी भूमिका को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है। पॉलिसी शून्य होने के कारण अक्सर असुरक्षित छोड़ दिया जाता है यद्यपि प्रवासी कार्यबल राष्ट्रीय गौरव के प्रत्यक्ष चिह्नों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, फिर भी उनके अधिकारों को नियंत्रित करने वाली नीतियों का घोर अभाव है।

अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979, इस विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करने वाला एकमात्र कानून है। हालाँकि, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, न्यूनतम मजदूरी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं की रोकथाम के लिए इसके प्रावधान अक्सर अधूरे रह जाते हैं।

प्रवासी श्रमिकों के साथ उनकी मानवता पर विचार किए बिना एक नौकरी मशीन की तरह व्यवहार किया जाता है। सरकारी प्रणालियाँ अक्सर प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों और परिवर्तनों की परवाह नहीं करतीं। प्रवासी श्रमिकों को न केवल कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती बल्कि उन्हें शहर के प्रतिकूल वातावरण में भी संघर्ष करना पड़ता है। शहर सड़कों और इमारतों जैसे निर्माण के लिए प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इन शहरों में इन प्रवासी श्रमिकों की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सहायता नहीं होती है। यहां स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सहायता, रहने के लिए अच्छे स्थान, सुरक्षा उपाय या बच्चों की देखभाल की सुविधाएं नहीं हैं। इससे प्रवासी श्रमिकों को सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की दुर्दशा विशेष रूप से चिंताजनक है। शिशुओं को बड़े बच्चों की देखभाल में छोड़ दिया जाता है, जिनके पास स्वयं सार्थक शैक्षिक गतिविधियों तक पहुंच नहीं होती। इससे असुविधा का एक चक्र निर्मित होता है, जहां शिक्षा के अवसरों की कमी उनके माता-पिता द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों से मुक्त होने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए, एक टूटा हुआ अंग अक्सर कामकाजी जीवन के अंत का संकेत देता है। कार्यस्थल पर लगी चोटों के लिए शायद ही कभी पर्याप्त सहायता या चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हो पाती हैं। घायल श्रमिक अपने घर लौटने के लिए बाध्य होते हैं, तथा उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक त्वरित और आवश्यक पहुंच बहुत कम उपलब्ध होती है। गांवों से शहरी क्षेत्रों की ओर मौसमी प्रवास की आवश्यकता, प्रवासी श्रमिकों के समक्ष चुनौतियों को और बढ़ा देती है। शहरी आवास की स्थिति अक्सर बहुत खराब होती है, जिससे शहर का मौसम दुख का एक अतिरिक्त स्रोत बन जाता है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए काम से परे जीवन की गंभीर वास्तविकताएं तत्काल ध्यान देने और व्यापक समाधान की मांग करती हैं। विचारशील शहरी नियोजन को कार्यस्थलों से आगे बढ़कर प्रवासी श्रमिकों के जीवन के संपूर्ण आयाम को शामिल करना चाहिए, जिससे न केवल रोजगार बल्कि सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध हो सके। बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की उपेक्षा, घायल श्रमिकों के लिए सहायता की कमी, तथा शहरी आवास की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियों की आवश्यकता को रेखां-कित करती है। उनकी विविधता का केवल जश्न मनाने के बजाय, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए एक ही नीति के दृष्टिकोण से हटकर सूक्ष्म नीतियों की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, जो प्रवासी श्रम शक्ति की जटिलताओं पर विचार करें।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

घूँघट की बगावत

19 जनवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

2

अफगानिस्तान के साथ भारत के जुड़ाव और तालिबान

तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद-रोधी और संपर्क जैसे राष्ट्रीय हितों को सहायता, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित करने वाले एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को उजागर करता है। रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए, भारत की अफगानिस्तान नीति विकसित वास्तविकताओं के अनुकूल है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानवीय आवश्यकताओं के अवलोकन (2023) में उल्लिखित विकासात्मक सहायता प्रदान करते हुए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव राष्ट्रीय हितों और मानवीय मूल्यों जैसे संकट के दौरान मानवीय सहायता के बीच संतुलन को दर्शाता है। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 50, 000 मीट्रिक टन गेहूँ और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की, जो संकट के बीच अफगान लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान धरती का इस्तेमाल उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जुड़ाव मानवीय सहायता और आतंकवाद-रोधी प्रयासों दोनों को प्राथमिकता देता है। बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं में भारत के निवेश ने क्षेत्रीय स्थिरता और अफगान नागरिकों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के उसके दोहरे उद्देश्य को उजागर किया। सलमा बाँध और इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान अफगान पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

भारत लगातार अफगानिस्तान को स्थिर करने और सद्भावना बनाए रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देते हुए अपने भू-राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान नेतृत्व से जुड़ता है। भारत अकादमिक आदान-प्रदान के माध्यम से अफगान छात्रों का समर्थन करता है और चिकित्सा पर्यटन की सुविधा देता है, जो दीर्घकालिक सांस्कृतिक और मानवीय सम्बंधों को दर्शाता है। हजारों अफगान छात्र भारत में शिक्षित होते हैं, जो लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत के जुड़ाव का आगे का रास्ता क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत को अफगान स्थिरता सुनिश्चित करने और पाकिस्तान या चीन जैसे विरोधी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए मध्य एशिया, ईरान और रूस को शामिल करते हुए बहुपक्षीय प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए। काबुल में राजनयिक मिशनों को मजबूत करना और उदारवादी तालिबान गुटों के साथ संवाद बढ़ाना सम्बंधों और मानवीय सहायता वितरण को संतुलित कर सकता है।

अफगानिस्तान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों को फिर से खोलना आपसी समझ के केंद्र के रूप में काम कर सकता है। स्थिरता में आर्थिक निवेशः अक्षय ऊर्जा, कृषि और छोटे उद्यमों में निवेश का विस्तार भारत के क्षेत्रीय लक्ष्यों के साथ सरेखित करते हुए अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकता है। अफगान सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने से रोजगार पैदा हो सकते हैं और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो सकती है। भारत को स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहायता बढ़ानी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके। भारत को तालिबान पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आतंकवादी संगठनों को बेअसर किया जा सके और उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने पर सहयोग करने से भारत के सुरक्षा उद्देश्यों को बढ़ावा मिल सकता है।

भारत-अफगानिस्तान सम्बंधों में कई बाधाएँ हैं, जिनमें पाकिस्तान की भूमिका शामिल हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती उपस्थिति को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए खतरा मानता है, तथा उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सम्बंधों को गहरा करने के भारत के प्रयासों को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है। भारत और अफगानिस्तान दोनों ही आतंकवाद के निशाने पर हैं और अफगानिस्तान में अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों की निरंतर उपस्थिति भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब और कम विकसित देशों में से एक है और सलमा बाँध और संसद भवन जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और देश में निवेश करने के भारत के प्रयास सुरक्षा मुद्दों, भ्रष्टाचार और अन्य चुनौतियों के कारण बाधित हुए हैं। हाल के वर्षों में चीन अफगानिस्तान में तेजी से सक्रिय हो गया है और इससे क्षेत्र में तालिबान के साथ चीन के बढ़ते प्रभाव और जुड़ाव को लेकर भारत में चिंताएँ पैदा हो गई हैं। अफगानिस्तान विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है और मादक पदार्थों के व्यापार ने इस क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत और अफगानिस्तान दोनों प्रभावित हुए हैं।

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। भारत ने अब तक केवल तालिबान को अलग-थलग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालाँकि, एक सीमा के बाद, यह विकल्प कम लाभ देगा, क्योंकि कई अन्य देश अब तालिबान से जुड़ना शुरू कर रहे हैं और भारत अफगानिस्तान में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक है। तालिबान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ सम्बंध हैं। तालिबान के साथ बातचीत से भारत में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भारतीय चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। तालिबान ने भारत को काबुल में अपना मिशन पुनः खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, देश के लिए सीधी उड़ानें पुनः शुरू कीं तथा अफगान सैन्य प्रशिक्षुओं को भी स्वीकार किया। भारत को अफगानिस्तान के प्रति एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक आयामों को एक व्यापक रणनीति के ढांचे के भीतर एक सुसंगत समग्रता में पिरो सके।

भारत की अफगान नीति क्षेत्र में भारत के रणनीतिक लक्ष्यों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक परिवेश की स्पष्ट समझ पर आधारित होनी चाहिए।

दोनों पक्षों यानी भारत और तालिबान के लिए यह आवश्यक है कि वे एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखें और कूटनीतिक और आर्थिक सम्बंधों में सुधार करें। भारत को अफगानिस्तान में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, खास तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। इससे अफगान अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी, साथ ही अफगानिस्तान के साथ भारत की आर्थिक भागीदारी भी गहरी होगी।

भारत की संतुलित अफगानिस्तान नीति मानवीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक चिंताओं को सम्बोधित करने में इसकी व्यावहारिकता को दर्शाती है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान के साथ जुड़ाव सतर्क लेकिन आवश्यक है। भविष्य के प्रयासों में भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के अनुरूप समावेशी विकास पर जोर देना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय और वैश्विक जिम्मेदारियाँ निरंतर शांति और सहयोग के लिए सरेखित हों।

-प्रियंका सौरभ

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। भारत ने अब तक केवल तालिबान को अलग-थलग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालाँकि, एक सीमा के बाद, यह विकल्प कम लाभ देगा, क्योंकि कई अन्य देश अब तालिबान से जुड़ना शुरू कर रहे हैं और भारत अफगानिस्तान में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक है। तालिबान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ सम्बंध हैं। तालिबान के साथ बातचीत से भारत में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भारतीय चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। तालिबान ने भारत को काबुल में अपना मिशन पुनः खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, देश के लिए सीधी उड़ानें पुनः शुरू कीं तथा अफगान सैन्य प्रशिक्षुओं को भी स्वीकार किया। भारत को अफगानिस्तान के प्रति एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक आयामों को एक व्यापक रणनीति के ढांचे के भीतर एक सुसंगत समग्रता में पिरो सके।

व्यंग्य : बाबाओं के बीच के अद्भुत और दिव्य साधु -संत

यह महाकुंभ काफी चर्चित रहने वाला है क्युकी इस बार इस महाकुंभ में अध्यात्म के साथ - साथ ग्लैमर और मसाले का तड़का भी लगने वाला है । हर्षा रिछारिया, लॉरेन जॉब्स , संत अभय सिंह, जैसे कई मुद्दे लोगो को कुंभ की ओर खीच रहे । इस महाकुंभ में कई साधक चर्चा का केंद्र बने हैं। एक आईआईटी बाबा भी इस महाकुंभ की ही देन है जो कुंभ में इंटरव्यू के दौरान सोशल मीडिया पर पैदा हुए इंट्रेस्ट से वायरल हुए है उधर एक मनका बेचने वाली पगलेट किस्म की तरुणी मोनालिसा भी खूब वहावहाई हवा हवाई रस मलाई खा रही । इन सबने कुम्भ मेले को गंध मचा के रख दिया है। लैपटॉप बाबा, कंप्यूटर बाबा, मोबाइल बाबा और पेजर बाबा का अलग स्वेग है । इन सबने भीड़ का सारा मजमा अपनी ओर खींच रखा है।उधर दूसरी ओर किसी के मुंह में भी माइक घुसेड़ देने वाले यूट्यूबर्स, रीलबाजों और पत्रकारों को महाकुंभ में अच्छा 'प्रसाद' मिल रहा है । मस्त मलंग बाबाओं की ओर से जिस तरह इन्हें दुत्कारा-दौड़ाया जा रहा है वो देखना 'परम आनंद' देने वाला है । मेला खतम होने के बाद सब कपूर की तरह उड़ खतम हो जायेंगे बस रह जायेंगी मेरी लिखी ये आर्टिकल जो आपको यह सब याद दिलाती रहेगी । यही बात हर उस सामर्थ्यवान पर लागू होती है जो सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद उसे तज देने का अनासक्त भाव रखता है। अडानी ने कुंभ में प्रतिदिन एक लाख लोगों को भोजन कराने का संकल्प किया और चार दिन के अंदर ही हिंडेनबर्ग स्वाहा हो गया। अखिलेश यादव रात्रि के प्रहर में कुंभ स्नान का दिव्य लाभ लेना चाह रहे थे क्युकी दिन में योगी बाबा उन्हे पहचान जाते ।महाराजा हरिश्चंद से लेकर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध से लेकर आजतक एक लंबी परम्परा हमको देखने को मिलती जहां राज पाट को तृण समझ कर नदी के घाट पर दान तप हेतु जाया गया। उस राह पर चला गया जो वन, कष्ट, संघर्ष और बोध की तरफ जाती है। वास्तव में त्याग का अर्थ दरिद्रता नहीं है। आपके पास भोग के लिए सब कुछ होते हुए उनके प्रति अनासक्त रहना ही त्याग है। संन्यासी बनने के क्रम में तुलसी बाबा एक चौपाई में लिखते हैं कि, नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ मुड़ाई भए संन्यासी।। अर्थात जब सब खो गया फिर तो अपने आप वैराग्य जाग जाता है, असली वैराग्य वह है जो सब कुछ होने के बाद जागता है। ऐसे लोग जिनका पेशा केवल लेखन अथवा साहित्य ही है, वह यदि धीरे धीरे राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपना विचार त्याग चुके हैं, उसका यह भी अर्थ नहीं है कि वह नासमझ हो गए हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उन्हें राइट से जिस व्यवसाय की उम्मीद थी, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए वह दूसरी दिशा में अपना व्यापारिक लाभ देखकर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे लोगों को समझा समझाकर आप थक जायेंगे लेकिन वह नहीं मानेंगे, क्यूंकि आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसे आप नहीं जगा सकते। राकेश यादव अजमगढ़ियां का वाकया देख लीजिए कट्टर समाजवादी बनने के चक्कर में बेचारा घनचक्कर हुआ फिर रहा ।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर

मेले में जिधर जाइए, उधर जाम, परेशान श्रद्धालु

महाकुंभ नगर (प्रयागराज)। समय दोपहर 2:07 मिनट, स्थानः ऐरावत द्वार चौराहा, सेक्टर-20। सलोरी निवासी महेश चंद्र मिश्रा दो बच्चों व पत्नी संग बाइक से जा रहे थे कि बैरिकेडिंग देख रुकना पड़ा। पूछने पर पुलिसकर्मियों ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट है, इसलिए रास्ता बंद किया गया है। कुछ ही देर में वहां चारों ओर वाहनों की कतार लग गई।

ज्वलंत प्रश्न: युवा जोड़ों की निजता की समस्या

विवाह पूर्व सम्बंधों में रहने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, विभिन्न लिंगों के व्यक्ति जो दोस्त, सहकर्मी या चचेरे भाई हैं, वे भी एक साथ यात्रा कर सकते हैं और उन्हें ऑयो की सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। भारत में युवा जोड़ों के लिए गोपनीयता का मुद्दा सामाजिक मानदंडों और कानूनी अधिकारों के बीच एक गहरे संघर्ष को उजागर करता है। ऑयो ने घोषणा की कि अविवाहित जोड़ों को अब उसके साझेदार होटलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। होटलों को स्थानीय संवेदनशीलता के आधार पर इस नियम को लागू करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह निर्णय नागरिक समाज समूहों और नागरिकों के अनुरोधों के कारण लिया गया, जिन्होंने कंपनी से ऐसी नीति अपनाने का आग्रह किया। शुरूआत में, यह नीति केवल उत्तर प्रदेश के मेरठ के होटलों पर लागू होगी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ऑयो अपने आवेदन को अन्य शहरों में भी लागू कर सकती है। यह वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव है। गोपनीयता और सम्बंधों पर कानूनी दृष्टिकोण विवाह-पूर्व सम्बंधों की मान्यता है। विभिन्न निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह-पूर्व सम्बंधों में प्रवेश करने के व्यक्तियों के अधिकार को मान्यता दी है। हालाँकि, ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या इस नीति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले लोग संविधान में या अन्यथा कानूनी उपाय पा सकते हैं।

हाल ही में, ऑयो ने घोषणा की कि अविवाहित जोड़ों को उसके साझेदार होटलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पायल कपाड़िया की पुरस्कार विजेता फिल्म ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट एक युवा जोड़े, अनु और शियाज की यात्रा को दर्शाती है, जो निजी स्थान पाने के लिए संघर्ष करते हैं। जबकि पात्र काल्पनिक हैं, उनकी समस्या भारत भर में विवाह-पूर्व सम्बंधों में कई युवाओं द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकता है, जहाँ गोपनीयता एक दुर्लभ वस्तु है। हाल ही में एक लोकप्रिय होटल एग्रीगेटर ऑयो द्वारा लागू की गई नीतियों के कारण गोपनीयता के लिए संघर्ष और भी बदतर होने की उम्मीद है। भारत में युवा जोड़ों के लिए गोपनीयता का मुद्दा सामाजिक मानदंडों और कानूनी अधिकारों के बीच एक गहरे संघर्ष को उजागर करता है। ऑयो ने घोषणा की कि अविवाहित जोड़ों को अब उसके साझेदार होटलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। होटलों को स्थानीय संवेदनशीलता के आधार पर इस नियम को लागू करने की स्वतंत्रता दी गई है।

सभी जोड़ों को चेक-इन के समय ₹सम्बंध का वैध प्रमाण₹ प्रस्तुत करना होगा, जो कि स्थानांतरण का तत्काल कारण है। ऑयो ने बताया कि यह निर्णय नागरिक समाज समूहों और नागरिकों के अनुरोधों के कारण लिया गया, जिन्होंने कंपनी से ऐसी नीति अपनाने का आग्रह किया। शुरूआत में, यह नीति केवल उत्तर प्रदेश के मेरठ के होटलों पर लागू होगी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ऑयो अपने आवेदन को अन्य शहरों में भी लागू कर सकती है। यह वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव है। 'सम्बंध का वैध प्रमाण' प्रदान करने की व्यावहारिकताओं से परे, यह स्पष्ट है कि ऑयो पार्टनर होटलों को उनके वैवाहिक स्थिति के आधार पर ग्राहकों के साथ भेदभाव करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हालाँकि, ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या इस नीति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले लोग संविधान में या अन्यथा कानूनी उपाय पा सकते हैं।

गोपनीयता और सम्बंधों पर कानूनी दृष्टिकोण विवाह-पूर्व सम्बंधों की मान्यता है। विभिन्न निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह-पूर्व सम्बंधों में प्रवेश करने के व्यक्तियों के अधिकार को मान्यता दी है। शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम. (2020) में, न्यायालय ने पुष्टि की कि संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तियों को अपने साथी चुनने का अधिकार शामिल है, ' चाहे विवाह के भीतर या बाहर। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) मामले ने सभी व्यक्तियों के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और यौन साहचर्य के अधिकार को मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों ने जोर देकर कहा है कि अनुच्छेद 21 से प्राप्त गोपनीयता, सम्मान और स्वायत्तता के अधिकार लोगों को सहमति से, अंतरंग या यौन सम्बंधों में संलग्न होने, अपने साथी के साथ सहवास करने की स्वतंत्रता देते हैं यदि वे चुनते हैं। कई अविवाहित जोड़ों के लिए, होटल सेवाओं का उपयोग करना इन अधिकारों का प्रयोग करने का एक तरीका है। विवाह पूर्व सम्बंधों में रहने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, विभिन्न लिंगों के व्यक्ति जो दोस्त, सहकर्मी या चचेरे भाई हैं, वे भी एक साथ यात्रा कर सकते हैं और उन्हें ऑयो की सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है।

मौलिक अधिकारों की प्रवर्तनीयता संवैधानिक योजना के तहत, संविधान के भाग ~~क~~क्क में निहित मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य और उसके साधनों के खिलाफ लागू करने योग्य हैं, न कि गैर-राज्य अभिनेताओं के खिलाफ। जब राज्य उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो नागरिक अदालतों से संवैधानिक उपचार मांग सकते हैं। हालांकि, ये अधिकार उन मामलों तक विस्तारित नहीं होते हैं जहाँ कोई निजी पक्ष उनके प्रयोग में बाधा डालता है। संवैधानिक अधिकारों को आम तौर पर ₹ऊर्ध्वाधर₹ तरीके से (यानी, राज्य के खिलाफ) लागू माना जाता है, न कि ₹क्षैतिज₹ तरीके से (यानी, निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच)। संविधान में तीन स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं जो अधिकारों के पारंपरिक ₹ऊर्ध्वाधर₹ मॉडल से अलग हैं: अनुच्छेद 15 (2) : सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुँचने में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार निजी पक्षों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है, जिससे क्षैतिज अधिकारों का दायरा बढ़ जाता है। जबकि अनुच्छेद 15 (2) धर्म, जाति और अन्य सूचीबद्ध आधारों पर भेदभाव को रोकता है, यह स्पष्ट रूप से वैवाहिक स्थिति को कवर नहीं करता है, जिससे ऑयो की नीति जैसे मामलों में इसकी प्रयोज्यता में अस्पष्टता बनी रहती है। निजी संस्थाओं के खिलाफ अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए कौशल किशोर निर्णय के निहितार्थ अस्पष्ट हैं। सुसंगत न्यायशास्त्र की कमी से यह अनिश्चित हो जाता है कि क्या अविवाहित व्यक्ति ऐसे मामलों में अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

वर्तमान कानून सीमित सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना महिलाओं को दिए जाने वाले अधिकार। हालाँकि, एक व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून की आवश्यकता है: वैवाहिक स्थिति, लिंग, जाति, यौन अभिविन्यास या अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव से व्यक्तियों की रक्षा करना। निजी लेनदेन पर लागू करें, जिसमें आवास, रोजगार और वाणिज्यिक सेवाएँ शामिल हैं। संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता निजी अभिनेताओं की सक्षम परिस्थितियों को बनाने की इच्छा पर निर्भर करती है। वैवाहिक स्थिति, धर्म या लिंग पहचान जैसी विशेषताओं पर भेदभाव न केवल होटल सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करता है, बल्कि आवास, रोजगार और संपत्ति के स्वामित्व को भी प्रभावित करता है। इसे सम्बोधित करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करने के लिए विधायी और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। सामाजिक मानदंड अक्सर बहुमत द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें प्राथमिकता देने से अल्पसंख्यक समुदायों के मूल्यों को कम करते हुए बहुमत के मूल्यों को बढ़ाने का जोखिम होता है। सहिष्णुता की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक मानदंड कठोर हो सकते हैं। समाज को अधिक सहिष्णुता को अपनाना चाहिए और कानूनी अस्पष्टताओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

बहुमत का अत्याचार अक्सर निजी क्षेत्र में उतना स्पष्ट नहीं होता है। किसी कार्य को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल सकती है, लेकिन संविधान हमें इसे करने का अधिकार देता है। कानून को-चाहे वह किसी भी रूप में हो-इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।

- डॉ. सत्यवान सौरभ,

तरक्की के बरक्स पोषण की चुनौती

विजय गर्ग

रपट में कहा गया है भारत में गरीबी और पोषण से संबंधित विभिन्न अध्ययन रपटों में यह तथ्य रेखांकित हो रहा है कि गरीबी में लगातार कमी आ रही है, लेकिन लोगों के भोजन में पोषक तत्त्वों की कमी चुनौती बनी हुई है। 'स्टेट बैंक आफ इंडिया रिसर्च' द्वारा गरीबी पर जारी गरीबों को सीधे लाभान्वित करने वाले सरकारी सहायता कार्यक्रमों के कारण गरीबी में कमी आई है। वहीं विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (सोफी) रपट 2023 में कहा गया है कि भारत में पोषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2020 और 2022 के बीच 7.4 करोड़ लोग अल्पपोषण के शिकार थे। इस रपट का विश्लेषण दर्शाता है कि रोजाना दो बार भोजन की परिभाषा के अनुसार भारत में भूख की समस्या तुलनात्मक रूप से कम हुई है। यानी आबादी के बड़े हिस्से की अनाज संबंधी जरूरतें मोटे तौर पर पूरी पूरी हो रही हैं। मगर पोषक की कमी बनी हुई है। इसी प्रकार वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 125 देशों के बीच भारत को 111वां स्थान दिया गया है।

एसबीआइ रिसर्च की रपट में कहा गया है कि गरीबी में कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से हुई है। जहां वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7 फीसद और शहरी गरीबी 13.7 फीसद थी, वहीं वर्ष 2023-24 में ग्रामीण गरीबी घट कर 4.86 फीसद और शहरी गरीबी घट कर 4.09 फीसद पर आ गई। इस रपट के मुताबिक पिछले 14 वर्ष में आमदनी बढ़ने से, जहां शहरों में हर माह प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता खर्च (एमपीसीई) 3.5 गुना हो गया, वहीं यह ग्रामीण इलाकों करीब चार चार गुना हो गया है। वर्ष 2009-10 2023-24 के बीच शहरी इलाकों में उपभोक्ता खर्च 1984 रुपए से बढ़ कर 6996 रुपए और ग्रामीण इलाकों में यह 1054 रुपए से बढ़ कर 4122 रुपए हो गया। ऐसे में शहरों की तुलना में गांवों में यह खर्च ज्यादा है।

गौरतलब है कि बीती चार जनवरी को प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कहा था देश में ग्रामीण गरीबी तेजी से कमी आ रही है। यह पिछले वर्ष 2024 में घट कर पांच फीसद से भी कम रह गई है। साथ ही ग्रामीणों की आमदनी और क्रयशक्ति बढ़ी है। गांवों के लाखों घरों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। लोगों को डेढ़ लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। डिजिटल तकनीक की मदद से बेहतरीन डाक्टर और अस्पताल भी

हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि यद्यपि गरीबों के सशक्तीकरण के साथ देश में प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी भारत दुनिया के उन प्रमुख दस देशों में शामिल जहां बीते बीस वर्षों में लोगों की आय में असमान इजाफा हुआ है। देश करोड़ों गरीबों के लिए हमें ऐसी नीतियां चाहिए, जो उनके लिए पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन के वितरण, उपलब्धता तय करने और उसे किफायती रखने में मददगार हो सकें।

गांवों से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए देश को किसानों को तीन लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। बीते दस वर्षों में कृषि ऋण साढ़े तीन गुना बढ़ गए हैं। अब पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। बीते दस वर्षों में फसलों पर दी जाने वाली सबसिडी और फसल बीमे की राशि को बढ़ाया गया है। स्वामित्व योजना जैसे अभियान चलाए गए हैं, जिनके जरिए गांवों के लोगों को संपत्ति के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, 'स्टार्टअप इंडिया' और 'स्टैंड अप इंडिया' जैसी योजनाओं के जरिए मदद की जा रही है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने उनकी गरीबी को कम करने अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज दिया जाना सुनिश्चित किया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को व्यवस्थित में रूप से निशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की भूमिका प्रभावी बनाई गई है। देश भर में मौजूदा पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। वर्ष 2016 से राशन की दुकानों में पाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनों की शुरूआत से रिसाव में कमी आई है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि डिजिटल इंडिया, स्वच्छ पेयजल और आयुष्मान भारत योजना और स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना अभियानों से देश में गरीबी में कमी आ रही है। खासतौर से करीब 54 करोड़ से अधिक जनधन खातों, करीब 138 करोड़ आधार कार्ड और करीब 115 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं की शक्ति से सुगठित बेमिसाल डिजिटल ढांचा गरीबों के सशक्तीकरण में असाधारण भूमिका निभा रहा है। इसके बल पर देश गरीब लोगों के खातों में सीधे राहत राशि हस्तांतरित हो रही है। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी से लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा हो चुकी है। इन सबसे गरीबी में बड़ी कमी आई है और ग्रामीण भारत विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है।

वैश्विक रपटों में भी भारत में गरीबों के सशक्तीकरण और विकास से गरीबी में कमी आने और उत्पादकता में वृद्धि होने के विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की दुनिया में गरीबी संबंधी रपट में कहा गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या वर्ष 1990 में 43.1 करोड़ थी। यह घटते हुए 2021 में 16.74 करोड़ रह गई और वर्ष 2024 में करीब 12.9 करोड़ ही गई है। नीति आयोग की तरफ मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) 2024 के मुताबिक पिछले दस वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। दुनिया के ख्यात अर्थशास्त्री थामस पिकेटी का कहना है कि भारत में तेजी से बढ़ता विकास आम आदमी की आमदनी बढ़ा रहा है और गरीबी में तेजी से घटने की प्रवृत्ति उभर रही है।

लोक कल्याणकारी योजनाओं से गरीबी और भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायता मिली है, लेकिन अभी भी बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे करीब 15 करोड़ से अधिक गरीबों को सरकार के लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए और अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि यद्यपि गरीबों के सशक्तीकरण के साथ देश में प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी भारत दुनिया के उन प्रमुख दस देशों में शामिल जहां बीते बीस वर्षों में लोगों की आय में असमान इजाफा हुआ है। देश करोड़ों गरीबों के लिए हमें ऐसी नीतियां चाहिए, जो उनके लिए पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन के वितरण, उपलब्धता तय करने और उसे किफायती रखने में मददगार हो सकें। उम्मीद है कि सरकार वर्ष 2025 में देश से गरीबी और घटाने के लिए सशक्तीकरण योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के साथ नई योजनाओं और नए रणनीतिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ेगी। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार देश में बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे करीब पंद्रह करोड़ से अधिक लोगों को 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लक्ष्य पर ध्यान देगी।

-मलोट पंजाब

पशु चिकित्सा विभाग के सहायक पशु चिकित्सक की मानें तो पत्थलगांव में महज 30 लोगों ने ही अपने पालतु कुत्तों का पंजीयन करा रखा है। शेष कुत्ते को आवारा पशु के क्रम में ही माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग में पंजीकृत कुत्तों को नियमित रूप से दवा देने से उनके काटने के बाद खतरे का अंदेशा नहीं रहता है। इसके विपरीत आवारा कुत्तों के काटे जाने पर यदि मरीज की सुरक्षा के उपाय नहीं किए जाने से उसके लिए खतरे का अंदेशा बना रहता है। श्री पटेल ने बताया कि मौजूदा समय में पशु चिकित्सा विभाग से कुत्तों की दवा की आपूर्ति नहीं होने से उन्हें बाजार से दवा क्रय करने की सलाह देनी पड़ रही है।

कुत्ते बने आतंक के पर्याय

शहर के विभिन्न मोहल्लों में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। कई मोहल्लों में आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को काट कर घायल कर चुके हैं। इसके बाद भी नगर पंचायत ने इन कुत्तों से लोगों को राहत दिलाने की कोई पहल नहीं की है। आवारा कुत्तों से यहां दरापारा, चट्टानपारा, बंदियाखार, पुरानी बस्ती सहित अन्य मुहल्लों में रहने वाले लोग खासे दहशत में हैं।

आवारा कुत्तों के हमले के भय से छोटे बच्चों का बाहर खेलना भी बंद हो गया है। कई अभिभावक अपने बच्चों को कुत्तों के भय से स्कूल भेजने में भी चिंतित रहते हैं। बच्चों को साथ लाते वक्त हाथ में डंडा होने के बाद भी चेहरों पर भय की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। बीते एक सप्ताह से शहर के विभिन्न मोहल्लों में आए दिन आवारा कुत्तों के काटने की घटना हो रही हैं। पिछले दिनों यहां वार्ड क्रमांक 15 में 4 साल की बच्ची रामप्यारी को घर के सामने खेलते हुए आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर पैर को नोंच दिया था। इस बच्ची को निजी चिकित्सक के पास उपचार कराने में बच्ची के परिजनों को काफी रकम खर्च करनी पड़ी। यहां बिलाईटांगर में भी आवारा कुत्तों के ही एक झुंड ने कक्षा पांचवीं का स्कूली छात्र के हाथ में झपट्टा मार कर उसे घायल कर दिया था। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ जाने से शहर के लोगों में जगह जगह भय का वातावरण बना हुआ है।

दर्रापारा की महिलाओं का कहना था कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ जाने से उन्हें हर समय घर के दरवाजे बंद रखने पड़ रहे हैं। इन दिनों आवारा कुत्तों की अचानक भीड़ टूट पड़ने से बच्चों का भी घर के बाहर खेलना और घूमना बंद हो गया है। यहां प्रेम नगर में मोहम्मद शैफ कुरैशी के घर के समीप बकरे को भी कुत्तों के झुंड ने काट कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। निर्दलीय पार्षद विशु शर्मा का कहना है कि नगर पंचायत को आवारा कुत्तों की समस्या का निदान करने के लिए कई बार सुझाव दिया गया है, पर अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं होने से लोगों में आवारा कुत्तों का भय दूर नहीं हो रहा है।

बताया जाता है कि कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पंचायत की है लेकिन काफी दिनों से महानगर एवं नगर पंचायतों में कुत्तों तथा आवारा कुत्तों की धर-पकड़ नहीं होरही शहर के हर मुहल्ले वचौराहों पर यह झुंड के झुंड दिखाई देते हैं। लेकिन आंख मूंद कर गाड़ी का शीश चढ़ाकर चले जाते हैं।

अधिक काम करने वाले बीमारियों से ग्रस्त होंगे

सनातन परंपरा में मानव जीवन और उसकी कार्यक्षमता के संबंध में मानव-केंद्रित वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस परंपरा में हम विकास और भौतिकवाद की अंधी दौड़ में शामिल होकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अपितु स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाते हुए अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक उत्पादकता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सप्ताह में 70 या 90 घंटे कार्य करने से सेहत पर दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। 2021 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी लंबी कार्यावधि का विरोध करती है। विभिन्न शोध बताते हैं कि अत्यधिक काम करने वाले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद और हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। लंबे समय तक बैठ कर काम करने वालों में जीवनशैली संबंधी ऐसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति और कम होती प्रजनन क्षमता भी काम के अतिशय दबाव और नकारात्मक वातावरण की देन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और मशीनीकरण के इस युग ने निश्चित ही मानव जीवन तथा मानवीय संवेदनाओं पर प्रश्नचिह्न लगाया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विचारों का आदि-स्रोत मानव मस्तिष्क ही है। यदि हम नवीन तथ्यों का अनुसंधान करना चाहते हैं तो इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रखना होगा। यह तभी संभव होगा, जब वर्क-लाइफ बैलेंस होगा। मौलिक चिंतन स्वस्थ मस्तिष्क से ही संभव हो पाता है। हम एआइ और रोबोटिक्स आदि के द्वारा कार्यों को आसान तो बना सकते हैं, लेकिन उसी कार्य को नवीनता या मौलिकता के साथ नहीं कर सकते। मशीन मनुष्य की जगह नहीं ले सकती।

अवसाद और अकेलेपन से बचने के लिए व्यक्ति परिवार और प्रकृति के साहचर्य में अपने तन-मन को दुरुस्त करता है। काम के अनावश्यक दबाव के कारण जीवनशैली प्रभावित होती है। जीवन की उत्पादकता और उपलब्धियों को संपूर्णता में देखने की आवश्यकता होती है। परिवार और समाज से अलग व्यक्ति का न कोई व्यक्तित्व है और न ही अस्तित्व। परिवार और समाज में रहकर ही व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है तथा रचनात्मकता एवं उत्पादकता बढ़ती है। इसलिए पारिवारिक और पेशेवर जीवन में उचित तालमेल बनाना होगा। बहुत ज्यादा काम के घंटों से बच्चे भटकावग्रस्त और बुजुर्ग उपेक्षित और एकाकी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति समाज एवं राष्ट्र के लिए शुभ नहीं। संवाद के लिए बने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म भी संवादहीनता और अकेलेपन के कारक बनते जा रहे हैं। चूंकि कार्यजीवन में संतुलन से ही व्यक्ति समाज एवं संस्थान में सर्वोत्तम योगदान दे सकता है, इसलिए जरूरी है कि कंपनियां कर्मियों को उनकी आवश्यकता समझकर अपेक्षित अवकाश प्रदान करें।

आजकल वर्क-लाइफ बैलेंस पर बहस जोर पकड़ती जा रही है। इस बहस में कुछ दिग्गज उद्योगपतियों के बयान हतप्रभ करने वाले हैं। हम जानते हैं कि कोविड जैसी आपदा से निपटने के बाद हम सभी ने बहुत मुश्किल से अपने कार्य और परिजनों के मध्य समय का संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, परंतु पिछले दिनों लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने का विचार रखा। उन्होंने दांपत्य जीवन का मखौल उड़ाते हुए कहा कि आखिर आप कब तक अपनी पत्नी को निहारेंगे। उन्होंने रविवार के अवकाश को भी गैर-जरूरी बताया। लगता है कि उन्हें न तो मानव-प्रबंधन की पेशेवर समझ है और न ही उनके भीतर मानवीय संवेदनाएं हैं। शायद उनका भारतीय जीवन-पद्धति, जीवन-दर्शन के साथ-साथ मानव-प्रबंधन क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से भी कोई सराकोर नहीं। क्या वह मनुष्य को रोबोट से अधिक कुछ नहीं समझते? यह विडंबना ही है कि वह यह भी भुला बैठे कि रोबोट को भी देखभाल और रीचार्जिंग की आवश्यकता होती है। कामकाजी घंटों की बहस कुछ समय पहले इन्फोसिस के सहसंस्थापक एनआर नारायणमूर्ति ने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर पर अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराना है तो हमें सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। इसके बाद कई कारोबारी ऐसी पैरवी कर चुके हैं, मगर महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, आइटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी और ओयो के सह-संस्थापक रितेश अग्रवाल ने काम के घंटे बढ़ाने का विरोध करते हुए काम और जीवन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने की बात की है।

सनातन परंपरा में मानव जीवन और उसकी कार्यक्षमता के संबंध में मानव-केंद्रित वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस परंपरा में हम विकास और भौतिकवाद की अंधी दौड़ में शामिल होकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अपितु स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाते हुए अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक उत्पादकता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में हम यह भी देखते हैं कि जीवन और जीवन-मूल्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शारीरिक-मानसिक संतुलन को नहीं बिगड़ने देते, क्योंकि ह्यअति सर्वत्र वर्जयेत हमारे जीवन-दर्शन का लक्ष्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास है, न कि एकाग्र भौतिक विकास हमारा एकमात्र ध्येय है। यही कारण है कि हमारे यहां सफलता की जगह सार्थकता पर बल है। महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे भारतीय विचारकों के अनुसार जीवन के परम लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का स्वास्थ्य, संतुलन और समन्वय आवश्यक है। यही चरम सुख और परम वैभव का प्रशस्त पथ है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के मूल्यांकन का आधार विकास दर मात्र नहीं, बल्कि हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए। व्यक्ति न केवल परिवार बसाता है, बल्कि समाज से भी जुड़ता है। वह प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके जीवन को सरल एवं सरस बनाता है। वह जीव और जगत के मध्य संतुलन स्थापित करता है। दूसरी ओर, भोगवादी जीवन पद्धति मानव को मशीन के रूप में देखती है। मानव जीवन का मशीनीकरण होने से उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। यदि उपयोगितावादी दृष्टि से मानव जीवन को देखा जाएगा तो केवल मानसिक संताप बढ़ेगा। परिवार और समाज जैसी संस्थाएं भी संकटग्रस्त होंगी। उपयोगितावादी दृष्टि से समाज में विखंडनकारी और विभेदकारी जीवन पद्धति को प्रोत्साहन मिलता है।

रह कर देखो कभी कच्चे मकानों में

क्या रखा है तपते मैदानों में
घूम कर देखो कभी सुनसान वीरानों में
करवटें लेते रहते हो पक्की हवेलियों में
रह कर देखो कभी कच्चे मकानों में
कण कण गर्मी से झुलस रहा
घूमने आ जाओ कभी पहाड़ों में
गर्मी में तो लगता स्वर्ग जैसा यहां
बहुत आनंद आता यहां जाड़ों में
गर्मी में जब हर तरफ बरसती है आग
घने जंगल देते यहां शीतल ठंडी हवा
पहाड़ों पर मिलता है अजीब सा सकूँ
कल कल बहती नदियां झरने लगती जैसे कोई दवा
पेड़ों से गिरते पत्ते खड़ खड़ करते आवाज
कुदरत मानो बजा रही कोई अद्भुत साज
भीनी भीनी आती उपवन से फूलों की खुशबू
देखने को मिलता प्रकृति का अलग ही अंदाज
कच्चे घर में जहां होता था विश्वास और प्यार भरा
वहीं पक्के घरों में रहता है इंसान डरा डरा
रहना चाहते हैं एक दूसरे से दूर
सूख रहा रिश्तों का पेड़ जो रहता था कभी हरा भरा

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि प्र

महाकुंभ से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी

प्रयागराज में 45 दिनों तक चलने वाले इस समागम में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वित्तीय लेनदेन 2.5 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। 2019 के अर्धकुंभ में 1.2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लेनदेन हुआ था। महाकुंभ की एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि डिजिटल लेनदेन पर बहुत अधिक जोर रहेगा।

इस डिजिटल लेनदेन से गैर-संगठित क्षेत्र के लोगों की ऋण क्षमता बढ़ने से बैंकिंग क्षेत्र की व्यवस्था भी मजबूत होगी। होटल, रेस्तरां, परिवहन सेवाएं और टूर प्रदाताओं के साथ-साथ क्षेत्रीय हस्तशिल्प, कला और व्यंजनों के लिए बाजार से जुड़े लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस आयोजन से स्ट्रीट वेंडर, शिल्पकार और दुकानदार आदि 45 दिनों में ही आठ महीने से अधिक की आय आसानी से अर्जित कर लेगें। सीआइआइ की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के कुंभ में विभिन्न क्षेत्रों में छह लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला था। इस बार यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार महाकुंभ की तैयारियों में लगभग 45हजार परिवारों को रोजगार मिल चुका है।

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का केवल धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही विशेष महत्व नहीं है। यह अर्थव्यवस्था को भी एक नई उड़ान देने वाला भी है। इस महाकुंभ में विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का अदभुत संगम दिखाई दे रहा है। पारंपरिक परंपराओं के अस्तित्व से अनुकूलन करता महाकुंभ समय के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ता दिख रहा है। यूनेस्को द्वारा 2017 में कुंभ मेले को मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद से यह आयोजन विश्व के लोगों के लिए और आकर्षण का केंद्र बन गया है। कुंभ उनके लिए सदैव शोध एवं जिज्ञासा का विषय रहता है कि कैसे बिना निमंत्रण के ही इतने अधिक लोग एक साथ एक जगह एकत्रित हो जाते हैं?

महाकुंभ में डिजिटल तकनीक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर है। यहां करीब 500 पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं गंगा और कुंभ की

स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए हर घर से एक थैला, एक थाली द्वारा हरित कुंभ में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। महाकुंभ में आधुनिक तकनीक का प्रयोग केवल भीड़ को सुचारु रूप से प्रबंधित करने और सुरक्षा आदि के लिए ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि 11 भाषाओं में एआइ संचालित चैटबाट कुंभ सहायक महाकुंभ की समस्त आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करा रहा है। महाकुंभ को भव्य एवं सुगम बनाने पर सरकार द्वारा लगभग सात हजार करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इस निवेश से न सिर्फ तीर्थाटन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इसके गुणक प्रभाव से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज की देश के विभिन्न हिस्सों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही भारतीय रेलवे ने तीन हजार विशेष ट्रेनों को चलाया है।

प्रयागराज में गंगा पर छह लेन का ब्रिज, चार लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। हल्दिया-वाराणसी जलमार्ग को प्रयागराज तक विस्तार दिया गया है। सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए विभिन्न विकास योजनाओं पर व्यय के साथ बड़े-बड़े उद्योगपति भी अपनी-अपनी वस्तुओं की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर रहे हैं।

महाकुंभ में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन से भी राज्य और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, दोनों के राजस्व में वृद्धि होगी। महाकुंभ के लिए टूर आपरेटरों द्वारा अनेक प्रकार के आकर्षक टूर पैकेज की पेशकश की जा रही है। प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्री केवल महाकुंभ तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेगें। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आदि अन्य स्थलों पर घरेलू एवं विदेशी मेहमानों के आने से सरकार को लगभग 200 करोड़ से अधिक आय सृजित होने की संभावना है।

कुंभ मेले का सर्वाधिक आकर्षण स्थानीय उत्पादों के स्टाल होते हैं। कुंभ एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा जा सकता है। इसके लिए बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से स्थानीय उद्योगों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

महाकुंभ में लोगों द्वारा गरीबों एवं वंचितों को अन्न एवं वस्त्र के दान का भी विशेष महत्व होता है। श्रद्धालुओं द्वारा संतों को भी दान दिया जाता है। भंडारे जैसी गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति या समाज ही नहीं, बल्कि पूरा देश ही उठ खड़ा होता है। इस सामाजिक चेतना को भले ही आर्थिक मानकों पर न मापा जा सके, पर ये गतिविधियां भी आर्थिक मापदंड का आधार मजबूत करती है।

महाकुंभ से देश की जीडीपी में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होने के साथ ही अन्य दूरगामी आर्थिक प्रभाव होंगे, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिकी को एक ट्रिलियन डालर वाले लक्ष्य के और निकट लाएंगे। महाकुंभ में आर्थिक प्रभावों से अधिक सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम्-की मूल भावना के और अधिक निकट लाएगा।

घूँघट की बगावत

19 जनवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

4

इस नए वर्ष में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना का काम आगे बढ़ने के आसार हैं।

डिजिटल जनगणना: देश और समाज के लिए एक सौगात

लोगों को भ्रमित करने के लिए जाति आधारित जनगणना की जो बात अब कांग्रेस कर रही है, वह 2011 के मनमोहन सिंह सरकार के समय में हुई भी थी, लेकिन उसका डाटा कभी जारी नहीं किया गया। शायद आंकड़े कांग्रेस के एजेंडे के अनुरूप नहीं रहे होंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार हर तरह की रिसर्च के बाद पुरानी गलतियों में सुधार के साथ पहली बार डिजिटल जनगणना की तैयारी में जुटी है तो भ्रम फैलाकर क्रेडिट लेने का प्रयास शुरू हो गया है। जब देश पर अंग्रेजों का शासन था तो ब्रिटिश सरकार बांटो और राज करो के सिद्धांत पर चलती थी। जातियों के आधार पर सामाजिक विभाजन के इरादे से तब जाति आधारित जनगणना कराई गई। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के हित में नीति बनाने की नीयत कभी नहीं थी। लक्ष्य था भारत पर जैसे-तैसे शासन करना और उसे सामाजिक रूप से विभाजित करना। जब देश आजाद हुआ, तो नेहरू सरकार ने अपने सोच में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया। 2014 से भारत ने बड़े बदलाव का दौर देखना शुरू किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में जाति आधारित सर्वे के लिए हरी झंडी दिखाई। नीतीश कुमार ने इस काम को अंजाम दिया।

क्रेडिट लेने वालों ने तब भी लोगों को भ्रमित किया। वे अब भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कितनी दूरदृष्टि रखते हैं, यह नई जनगणना में दिख जाएगा। इसकी पुष्टि इससे होती है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने खुले मंच से यह स्वीकार किया कि अब जिस तरह की जनगणना मोदी सरकार कराने वाली है, संप्रग सरकार के रहते कांग्रेस ने जनगणना में वैसा जातिगत रिकॉर्ड नहीं जुटाकर गलती की थी। इस नए वर्ष में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना का काम आगे बढ़ने के आसार हैं। दस साल के अंतराल के हिसाब से 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी। यह इसलिए नहीं हो सकी, क्योंकि 2020 और 2021 में पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी। भारत भी उसकी चपेट में था। ऐसे में जनगणना की तैयारी धरी रह गई। 2022 में भी कोविड को लेकर माहौल बना रहा, फिर संसदीय चुनाव आ गए, जिसमें बड़ी संख्या में उसी सरकारी अमले को जुटना था, जो जनगणना करता है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी तो जनगणना होने की उम्मीद जगी। इस बार जो जनगणना होगी, वह पुरानी गलतियों को खत्म करने के साथ पीएम मोदी के सूत्र वाक्य ह्यसबका साथ, सबका विकासह्ण के नजरिये से होगी। इस बीच कांग्रेस की ओर से लोगों को जनगणना के नाम पर बरगलाने की कोशिश हो रही है। यह याद करना जरूरी है कि राजीव गांधी पिछड़ों के हित वाली नीतियों के खिलाफ थे। यही कारण था कि जब भाजपा के सहयोग से केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो भाजपा ने पिछड़ा वर्गों के हितों की रक्षा के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में अहम भूमिका निभाई। तब नेता विपक्ष के रूप में राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का भारी विरोध किया था।

जनगणना के जिस रूप की परिकल्पना की जा रही है, वह एक रिकॉर्ड होगा। ऐसा रिकॉर्ड जो हर समय डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, ताकि जिस समय जिस योजना पर विचार किया जा रहा हो, उसमें उसका उपयोग हो सके। समूह के आकार, भौगोलिक वितरण, लैंगिक संरचना और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड, जो भारत के सामाजिक तानेबाने की पूरी तस्वीर दिखा सके। दरअसल नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14ए के तहत सभी नागरिकों का पंजीकरण करना और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नेशनल पापुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर का उद्देश्य है। वन नेशन-वन इलेक्शन की जो बात अब आगे बढ़ चुकी है, उसके लिए भी यह जनगणना अत्यंत लाभकारी होगी। जनगणना में एकत्रित डिजिटल जानकारी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण और सामाजिक समूहों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का आधार बनेगी। यह जरूरी भी है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के जरिये 2000 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। 84वें संशोधन अधिनियम (2002) से इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया। यदि प्रस्तावित जनगणना शीघ्र शुरू होती है तो 2026 में इसका रिकॉर्ड जारी हो जाएगा। एक लंबे समय से सामाजिक समूहों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण पुरानी और आधी-अधूरी जानकारी पर निर्भर था, जो डिजिटल जनगणना के बाद ज्यादा संगठित संग्रह (डेटाबेस) होगा। यह डाटाबेस कई उद्देश्यों को साधेगा और जनोपयोगी भी होगा। जन्म से लेकर शिक्षा, रोजगार और यहां तक कि आयकर के लिए नीतियों के निर्धारण में इसकी अहम भूमिका होगी। विपक्ष यह कहकर भाजपा को निशाने पर लेता रहा है कि वह आरक्षण विरोधी है, लेकिन उसके फैलाए तमाम भ्रम दूर करते हुए आरक्षण को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त-वक्त पर सब कुछ साफ किया है। अधिक समावेशी, उत्तरदायी, न्यायसंगत और सुरक्षित समाज की रूपरेखा बनाने वाली **डिजिटल जनगणना देश और समाज के लिए एक सौगात** होगी। ऐसे में विपक्ष को जनगणना का इंतजार करना चाहिए।

वन नेशन-वन इलेक्शन की जो बात अब आगे बढ़ चुकी है, उसके लिए भी यह जनगणना अत्यंत लाभकारी होगी। जनगणना में एकत्रित डिजिटल जानकारी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण और सामाजिक समूहों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का आधार बनेगी।

इंसानों की तस्करी की त्रासदी वाला समाज कब तक?

कुछ माता-पिता बच्चों को सड़क पर भीख मांगने या सामान बेचने के लिए मजबूर करते हैं, और कुछ अपनी बेटियों को कर्ज चुकाने, समुदायों के बीच विवादों को सुलझाने या अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए विवाह या बाल यौन तस्करी के लिए बेच देते हैं या मजबूर करते हैं।

मानव तस्करी की बढ़ती शर्मनाक घटनाओं ने संवेदनहीन होते समाज की त्रासदी को उजागर किया है। इन घटनाओं को अभिभावकों एवं समाज की संवेदनहीनता और क्रूरता के रूप में देखा जा सकता है, वहीं आजादी के अमृत काल में भी मानव-तस्करी की घिनौनी मानसिकता के पांव पसारने की विकृति को सरकार की नाकामी माना सकता है।

राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन मानव तस्करी और आधुनिक दासता के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस एक ऐसे वैश्विक अपराध, त्रासदी एवं अभिशाप की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो दुनियाभर में मानव जीवन, परिवारों और समुदायों को डरावनी, खौफनाक एवं त्रासद अंधेरी दुनिया में धकेलता है। मानव तस्करी लाखों लोगों की आजादी और सम्मान को छीनता है, समाज को अनगिनत नुकसान पहुँचाता है, कानून और सुशासन को कमजोर करता है और अपराध को बढ़ावा देता है। मानव तस्करी में बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के इस्तेमाल के जरिए शोषण एवं उत्पीड़न शामिल है। मानव तस्करी कई रूपों में हो सकती है जिसमें यौन तस्करी, बाल यौन तस्करी, जबरन मजदूरी, ऋण बंधन, जबरन बाल मजदूरी, घरेलू दासता और बाल सैनिकों की अवैध भर्ती और उपयोग शामिल है। यह पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और बच्चों को सीमाओं के पार और देश के अंदर दोनों जगह प्रभावित करता है। मानव तस्करी के खिलाफ कानून और नीतियां बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रयास किए जाने अपेक्षित है।

वैश्विक स्तर पर, मानव तस्करी के शिकार पाँच व्यक्तियों में से एक बच्चा हैं हालांकि अफ्रीका और ग्रेटर मेकांग जैसे गरीब क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में, तस्करी के शिकार लोगों में से अधिकांश बच्चे ही हैं। इस बीच, दुनिया भर में मानव तस्करी के शिकार लोगों में से दो तिहाई महिलाएँ हैं। मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है और दुनिया के सबसे शर्मनाक अपराधों में से एक है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन के लिये अभिशाप है और सरकारों पर एक बदनुमा दाग एवं कलंक है। मानव तस्कर दुनिया के सभी कोनों से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को धोखा देते हैं और उन्हें हर दिन शोषणकारी अंधेरी परिस्थितियों एवं दुनिया में धकेलते हैं। जबकि मानव तस्करी का सबसे वीभत्स रूप यौन शोषण है, हजारों पीड़ितों को जबरन श्रम, घरेलू दासता, बाल मजदूरी एवं भीख मांगने के लिये मजबूर किया जाता है और ऐसे पीड़ितों के अंगों को निकालने के उद्देश्य से भी तस्करी की जाती है। अंतरराष्ट्रीय एनजीओ शोध के अनुसार, पापुआ न्यू गिनी के लगभग 30 प्रतिशत यौन तस्करी के शिकार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनमें से कुछ की उम्र 10 वर्ष से भी कम है। कथित तौर पर कतिपय परिवार या जनजाति के सदस्य यौन तस्करी या जबरन मजदूरी करवाते हैं। कुछ माता-पिता बच्चों को सड़क पर भीख मांगने या सामान बेचने के लिए मजबूर करते हैं, और कुछ अपनी बेटियों को कर्ज चुकाने, समुदायों के बीच विवादों को सुलझाने या अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए विवाह या बाल यौन तस्करी के लिए बेच देते हैं या मजबूर करते हैं।

दुनियाभर में हर साल करीब 6 लाख से 8 लाख लोगों की तस्करी होती है। दुनियाभर में पाए गए सभी मानव तस्करी के पीड़ितों में से 51 प्रतिशत वयस्क महिलाओं की संख्या है। भारत में वर्ष 2019 में, सरकार ने 5145 मानव तस्करी के पीड़ितों और 2505 मानव तस्करी के संभावित पीड़ितों की पहचान किए जाने की जानकारी दी, जोकि वर्ष 2018 में पहचान किए गए 3946 मानव तस्करी पीड़ितों और 1625 मानव तस्करी के संभावित पीड़ितों की तुलना में वृद्धि थी। इसके आगे भी मानव तस्करी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में वर्ष 2010 में राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार, प्रत्येक जनवरी को राष्ट्रीय गुलामी और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में नामित किया गया है। मानव तस्करी की बढ़ती शर्मनाक घटनाओं ने संवेदनहीन होते समाज की त्रासदी को उजागर किया है। इन घटनाओं को अभिभावकों एवं समाज की संवेदनहीनता और क्रूरता के रूप में देखा जा सकता है, वहीं आजादी के अमृत काल में भी मानव-तस्करी की घिनौनी मानसिकता के पांव पसारने की विकृति को सरकार की नाकामी माना सकता है। सरकार को बच्चों से जुड़े कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए एवं बच्चों के प्रति घटने वाली ऐसी संवेदनहीनता की घटनाओं पर रोक लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस देश में मानव तस्करी के जघन्य अपराध के रूप में बच्चों के साथ जो हो रहा है उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। उन्हें खरीदने-बेचने और उनसे भीख मंगवाने का धंधा, उनके शरीर को अपंग बनाने का काम, खतरनाक आतिशबाजी निर्माण में बच्चों का उपयोग, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, तंत्र-मंत्र के चक्कर में बलि चढ़ते मासूम बच्चे और उनका यौन शोषण। देश के भविष्य के साथ यह सब हो रहा है। लेकिन जब सरकार को ही किसी वर्ग की फिक्र नहीं तो इन मासूमों की पीड़ा को कौन सुनेगा? इस बदहाली में जीने वाले बच्चों की संख्या जहां देश में लाखों में है, वहीं जन्मते ही बच्चों को बेच देने की घटनाएं भी रह-रह कर नये बन रहे समाज पर कालिख पौतते हुए अनेक सवाल खड़े करती है। लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार मिलेंगे, लाखों बेघर, दर-दर की ठोकर खाते हुए आधुनिकता की चकाचौंध से कोसों दूर, निरक्षर और शोषित। बच्चों को बेच देने एवं तस्करी की घटनाएं कई बार ऐसी परतों में गुंथी होती हैं जिनमें समाज, परंपरागत धारणाएं, गरीबी और विवशता से लेकर आपराधिक संजाल तक के अलग-अलग पहलू शामिल होते हैं।

समाज में आज भी लड़के एवं लड़की को लेकर संकीर्ण एवं अमानवीय सोच व्याप्त है, झारखण्ड में एक दंपति को पहले से तीन बेटियां थी। सामाजिक स्तर पर मौजूद रूढ़ियों से संचालित धारणा के मुताबिक उस दंपति को एक बेटे की जरूरत थी। यानी तीन बेटियां उसकी नजर में महत्वहीन थी कि उससे बेटे की भरपाई हो सके। इसलिए उसने ऐसी सौदेबाजी कराने वाले मानव तस्कारों एवं दलालों के जरिए किसी अन्य महिला से उसका नवजात बेटा खरीद लिया। यानी मन में बेटा नहीं होने के अभाव से उपजे हीनताबोध और कुंठा की भरपाई के लिए कोई व्यक्ति पैसे के दम पर गलत रास्ता अपनाने से भी नहीं हिचकता। इसके अलावा, मानव तस्करी करने वाले गिरोह दूरदराज के इलाकों में और खासतौर पर गरीबी की पीड़ा झेल रहे लोगों के बीच अपने दलालों के जरिए बालक एवं बालिका खरीदने के अपराध में लगे रहते हैं। झारखण्ड, ओड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों के गरीब इलाकों में ऐसे तमाम लोग होते हैं, जिन्हें महज जिंदा रहने के लिए तमाम जद्दोजहाद से गुजरना पड़ता है। विश्व की बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनते भारत की सतह पर दिखने वाली अर्थव्यवस्था की चमक की मामूली रोशनी भी उन तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाती है?

मानव तस्करी की बढ़ती घटनाओं में बच्चों एवं बालिकाओं को बेचे और खरीदे जाने में जितने लोग, जिस तरह शामिल होते थे, वह नये बनते भारत के भाल पर एक बदनुमा दाग है। निश्चित रूप से इस मामले में मां की ममता एवं करूणा कठघरे में होती है, मगर कई बार अपने ही बच्चे के बदले पैसा लेने की नौबत आने में हालात भी जिम्मेदार होते हैं। वरना अपने बच्चे का सौदा करना किसी मां के लिए इतना आसान नहीं होता है।

झारखण्ड और ओड़ीसा सहित देश के अनेक हिस्सों के गरीब इलाकों से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिनमें कुछ हजार रुपए के लिए ही बच्चे को मानव तस्करों के हवाले कर दिया जाता है। सवाल है कि बच्चे को बेचने के पीछे क्या कारण होते हैं, उनके खरीददार कौन होते हैं और ऐसी सौदेबाजी को आमतौर पर एक संगठित गतिविधि के रूप में अंजाम देने में क्यों सफलता मिल जाती है। क्यों कानून का डर ऐसे मानव तस्कारों एवं अपराधियों को नहीं होता? क्यों सरकारी एजेंसियों की सख्ती भी काम नहीं आ रही है और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां प्रश्न कार्रवाई का नहीं है, प्रश्न है कि ऐसी विकृत सोच एवं अपराध क्यों पनप रहे हैं?

राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हुए हमें इस गुलामी एवं अभिशाप से मुक्ति में लगे संगठनों को आर्थिक मदद करनी चाहिए। हमें इस गुलामी को खत्म करने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। आज, मानव तस्करी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसलिए खुद को शिक्षित करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहिए।

पृथ्वी को परमाण हथियारों के अभिशाप से मुक्त किया जाए

हिरोशिमा के लोगों ने पहले तो एक बहुत तेज चमक देखी जिसके आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ गई। उसके बाद उन्हें लगा जैसे सूर्य की किरणों को उनसे छीनने के लिए एक गहरी धुंध छा गई। शायद उन्हें उस समय नहीं पता था कि धूल की इस परत में हजारों मनुष्यों और अन्य असंख्य जीवझजंतुओं के कण भी सम्मिलित थे, जिनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े इस विस्फोट ने तुरंत कर दिए थे। इस विस्फोट में तुरंत 70 हजार लोग मारे गए, पर तिल-तिल कर मरने वाले लोगों की संख्या तो इससे दो या तीन गुणा अधिक थी। ढाई लाख की आबादी वाले हिरोशिमा शहर में एक लाख 60 हजार लोग तुरंत मारे गए या बुरी तरह घायल हुए। अधिकांश अन्य लोगों ने और आने वाली पीढिक्ष्यों ने भी दीर्घकालीन बेहद दर्दनाक परिणाम झेले। हजारों लोगों ने जो यातना सही वह असहनीय थी। विस्फोट के केंद्र में तापमान तीन हजार से चार हजार डिग्री तक पहुंच गया,जबकि लोहा 1550 डिग्री पर पिघल जाता है। 15 वर्षीय बालिका मिशिको यामोका इस केंद्र से लगभग एक किमी. दूर थी तो भी उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। हिरोशिमा में रहने वाले जर्मन पादरी क्लीनसार्ज ने प्यास से कराहते लोगों की आवाज सुनी तो वे पानी लेकर दौड़े। वहां उन्होंने बीस व्यक्ति देखे जिनका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, जिनकी आंखों से द्रव्य पिघल कर गालों पर फैल गया था और इस कारण आंखें खोखली हो चुकी थीं। कुछ लोगों ने आग की विशाल लपटों को तेजी से अपने आवास क्षेत्रों की ओर लपकते देखा। दूर-दूर तक आग लगी हुई थी। एक अस्पताल में कराह रहे मरीजों को पोषक तत्वों की बहुत जरूरत थी पर आसपास जलती लाशों की सडक्षन के कारण वे गले के नीचे कुक्ष्छ उतार नहीं पा रहे थे। बढक्ष्ते जलझ्स्तर के कारण कहीं लोग डूब रहे थे तो कहीं आग में जल रहे थे। हजारों मकान और भवन ध्वस्त हो चुके थे। तब से अणु बम का प्रतीक बना एक भूरा खुंभीनुमा बादल घंटों तक पूरे शहर को आतंकित करता रहा। इन बेहद भयावह परिणामों के बावजूद शीघ्र ही अमेरिकी विमानों ने एक अन्य जापनी शहर नागासाकी पर भी अणु बम गिरा दिया। इन दोनों शहरों में तुरंत लगभग एक लाख लोगों की मृत्यु हो गई और दीर्घकालीन परिणामों से लगभग साढ़े तीन लाख लोगों की मृत्यु हो गई। अनुमान लगाया गया कि हिरोशिमा में एक ही अणु बम से उतनी मानवीय क्षति हुई जितनी सामान्य बमों से भरे हुए 279 बड़े विमान दस गुणा अधिक आबादी वाले शहर में कर सकते थे।

विश्व के लिए किसी एक बड़े खतरे की पहचान करनी हो तो यह निश्चय ही परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना से जुड़ा है। यदि इस समय विश्व में लगभग 13 हजार परमाणु हथियार हैं तो यदि ऐसे में कभी इनमें से पांच से दस प्रतिशत हथियारों का भी उपयोग वास्तव में हो गया तो विश्व में शायद ही कोई मनुष्य बच पाएगा। जो उस समय के विस्फोट आग और रेडिएशन से बच सके तो दीर्घकालीन असर से कुछ ही महीनों में मारे जा सकते हैं। अतः परमाणु हथियारों के इस विनाश की आशंका को रोकने को विश्व स्तर पर उच्चतम प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए।

अभी तक परमाणु हथियारों का उपयोग केवल दो बार हुआ-1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में। हालांकि ये आज के अधिकांश परमाणु हथियारों से

जरूरत इस बात की है कि विश्व में जितने परमाणु हथियार बनाए जा चुके हैं, उन्हें असरदार ढंग से नष्ट करने में वैज्ञानिकों की क्षमता को लगाया जाए ताकि शीघ्र से शीघ्र पृथ्वी को परमाणु शस्त्रों के अभिशाप से मुक्त किया जा सके। प्रायः कहा जाता है किसी भी चीज को बनाना कठिन है, नष्ट करना आसान है पर परमाणु हथियारों पर यह कहावत कतई लागू नहीं होती। इन्हें बनाना जितना कठिन है, इन्हें असरदार ढंग से नष्ट करना कई बार उससे भी कठिन और महंगा सिद्ध हो सकता है।

कहीं कम विध्वंसक थे पर इनमें से भी बहुत भंयकर तबाही हुई। 6 अगस्त, 1945 का दिन था। जापान के हिरोशिमा शहर में सूर्य की जीवनदायी किरणों ने एक नये दिन का आह्वान किया और उनसे आलोकित प्रभात में लोग अपने-अपने काम में लग गए पर यह दिन किसी और दिन जैसा नहीं था क्योंकि रात के तीन बजे ही अमेरिका की वायुसेना के कर्नल पाल ताईबत और रॉबर्ट लुई एक बी-२९ विमान में अब तक विश्व में निर्मित सबसे अधिक विनाशकारी शस्त्र लेकर हिरोशिमा के लिए रवाना हो चुके थे। एक क्रूर मजाक के तहत इस शस्त्र का नाम छोटा लड़का' या लिटल ब्वॉय' रखा गया था, पर था यह विश्व का पहला परमाणु बम। 31 हजार फीट की ऊंचाई पर उडक्ष्ते हुए शैतान का अग्रदूत बना यह विमान हिरोशिमा के ठीक ऊपर पहुंच गया और वहां से अणु बम को इस तरह गिराया गया जिससे हिरोशिमा के दो हजार फीट ऊपर रहते हुए ही उसका विस्फोट हो जाए और इस तरह अधिकतम विनाश सभंव हो।

कई दशकों तक हिरोशिमा और नागासाकी के लोग तरह-तरह की भीषण बीमारियों को अणु बम के दीर्घकालीन परिणाम के रूप में झेलते रहे। जगहझजगह से खून बहना, जख्मों का ठीक न होना, तेज बुखार से बार-बार पीड़ित होना-और सबसे बडक्ष हादसा तो यह कि तरहझतरह के कैंसरों में भयानक वृद्धि। कभी खून का कैंसर तेजी से बढक्ष्ता था, कभी त्वचा का कैंसर तो कभी कोई अन्य कैंसर। जो महिलाएं बम गिरने के समय गर्भवती थीं, उनमें से अनेक के बच्चे तरहझतरह की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त रहे। विशेषकर मंदबुद्धि बच्चों का जन्म अधिक हुआ। इस तरह के अनेक दीर्घकालीन असर मुख्य रूप में विकिरण या रेडिएशन के असर के कारण हुए। हिरोशिमा में केवल एक परमाणु बम ने कितनी तबाही की थी यह जानने के बाद यह तथ्य वास्तव में भयानक प्रतीत होता है कि आज विश्व में तरह-तरह की निरस्त्रीकरण की वाताओं और सम्मेलनों के बावजूद तेरह हजार परमाणु शस्त्र मौजूद हैं। परमाणु युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें किसी की विजय नहीं है जिसमें पूरी मानवता की पराजय है। जरूरत इस बात की है कि विश्व में जितने परमाणु हथियार बनाए जा चुके हैं, उन्हें असरदार ढंग से नष्ट करने में वैज्ञानिकों की क्षमता को लगाया जाए ताकि शीघ्र से शीघ्र पृथ्वी को परमाणु शस्त्रों के अभिशाप से मुक्त किया जा सके। प्रायः कहा जाता है किसी भी चीज को बनाना कठिन है, नष्ट करना आसान है पर परमाणु हथियारों पर यह कहावत कतई लागू नहीं होती। इन्हें बनाना जितना कठिन है, इन्हें असरदार ढंग से नष्ट करना कई बार उससे भी कठिन और महंगा सिद्ध हो सकता है। 1987-1991 और 1993 में अमेरिका और सोवियत संघ (या रूस) के बीच तीन महत्वपूर्ण समझौते अणु शस्त्रों और अन्य शस्त्रों को कम करने के बारे में हुए जिनका व्यापक स्तर पर स्वागत किया गया और जिनसे अनेक लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि अब काफी बडक्ष्े पैमाने पर अणु शस्त्र इन दोनों देशों में नष्ट किए जा रहे हैं पर वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने हुए मानवीय विकास रिपोर्ट 1994 ने जानकारी दी कि इन संधियों से तनाव कम तो हुआ है पर इनकी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। इनमें बताया गया है कि कुछ हथियारों या वारहैडों को इन्हें शत्रु तक पहुंचाने वाले वाहकों या प्रक्षेपास्त्रों से अलग कर दिया जाए पर इनमें यह निर्देश नहीं दिया गया है कि वारहैड को ही नष्ट कर दिया जाए। आगे यह रिपोर्ट और भी सटीक शब्दों में बताती हैइन तो अमेरिका के पास और न ही रूस के पास एक तकनीकी और राजनीतिक दृष्टि से मान्य योजना है जिसके तहत वारहैडों के विभिन्न हिस्सों को अलग किया जाए और नाभिकीय हिस्सों को नष्ट किया जाए। अतः ये वारहैड आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बने रहेंगे, यही आशंका है। वास्तव में परमाणु शस्त्रों को नष्ट करने से जुड़ी अनेक तकनीकी दिक्कतों और महंगे आर्थिक बजट के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए जिसके द्वारा इस कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी जा सके और विश्व के सभी इस क्षेत्र में क्षमता प्राप्त देशों और उनके वैज्ञानिकों को सब तरह के संकीर्ण स्वार्थों को छोड़कर इस अभियान में परस्पर सहयोग करना होगा।

महिलाओं के लिए रेवड़ियों की घोषणा

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए रेवड़ियों का ऐलान कर दिया है। कोई किसी से पीछे नहीं है। महिलाओं की याद चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को बहुत आती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक सभी वर्गों के वोट का दोहन उन लोगों ने कर लिया है। अब आधी आबादी ही बची है जिस–ाका वोट पाने के लिए येन केन प्रकारेण फुसलाना और रेवड़ियां बनी है।

यही कारण है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा ने यदि महिलाओं को प्रतिमाह हजार रुपए और गर्भवती महिला को 21 हजार देने का वादा किया है तो आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, उसका वादा है कि वह माताओं और बहनों को 2100 रुपए उनके अकाउंट में डालेगी। कांग्रेस भी कहा पीछे रहने वाली थी उसने भी अपने चुनावी घोषणापत्र में प्यारी दीदी योजना के तहत कई हजार रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है।

दिल्ली के 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए आगामी 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे जिसकी गणना 8 फरवरी को होगी। पिछले दो चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केन्द्र और कई राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा को हाशिए पर डाल दिया था और कांग्रेस की तो मोहनी ही नहीं होने दी थी। दिल्ली विधानसभा में 58 सीटें सामान्य है जबकि 12 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो लोकसभा चुनाव के पहले महिला को भी एक जाति बताया था। पहले बुजुर्ग महिलाओं और निराश्रित महिलाओं को समाज कल्याण के नाम से थोड़ी सी आर्थिक सहायता दी जाती थी। इस सहायता से उनके घरों में उनका महत्व बढ़ जाता था क्योंकि इस छोटी सी राशि से भी घरवालों को उम्मीदें लगी रहती थीं और जिन बुजुर्गों की उपयोगिता मूल्य घर में समाप्त हो चुका होता है उन्हें भी इसी के भरोसे मान-सम्मान, भोजन पानी और इलाज मिल जाता है। इस राशि से ये बुजुर्ग महिलाएं अपना धर्म-कर्म भी निपटा लेती थी जातियां और धर्म की अपेक्षा आधी आबादी की संख्या कहीं अधिक है

आधी आबादी का अपना अलग ही दर्द है, वैसे तो वे खुद के बजाय अपना परिवार के लिए अपनी जीवन व्यतीत करती है लेकिन जो महिलाएं घर के बाहर काम नहीं करती है पति बेटे पर आर्थिक रूप से आश्रित होती है।

यानी लगभग पचास प्रतिशत जो जाति धर्म की संख्या से परे है।

मध्यप्रदेश की लाडली बहना योजना ने भारतीय जनता पार्टी की सारी सत्ता विरोधी रूझान को समाप्त करके आश्चर्यचकित करते हुए भाजपा की सत्ता में वापसी करावी महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना ने भी भाजपा गठबंधन को सत्ता तक दोबारा पहुंचाया। झारखंड में महया सम्मान योजना में वृद्धि ने भाजपा की दाल गलने नहीं दी। जेल जाने जेल से आने भाजपा की तिकड़म के बावजूद दोबारा अपनी सरकार बनाने में हेमंत सोरेन कामयाब रहे।

आधी आबादी का अपना अलग ही दर्द है, वैसे तो वे खुद के बजाय अपना परिवार के लिए अपनी जीवन व्यतीत करती है लेकिन जो महिलाएं घर के बाहर काम नहीं करती है पति बेटे पर आर्थिक रूप से आश्रित होती है। महिलाओं की बुनियादी स्थिति आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर है क्योंकि न तो उनके पास धन होता है न धरती न सिर पर अपनी छत उनके पास जो कुछ भी होता है या तो अपना किया होता है या दूसरों का दिया होता है। यही कारण है कि वह ऐसे मामलों में परिवार की पसंद के वोट की सलाह को भी नहीं मानती है क्योकि उन्हें पता होता है कि बोट तो गोपनीय है उन्हें क्या पता चलेगा कि किसे दिया? यही कारण है कि उज्ज्वला योजना की शुरूआत में उत्तर प्रदेश चुनाव में गरीब तबके की और मुस्लिम महिलाओं ने भी भाजपा को 2017 में वोट किया था। जो भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आयी थी इसीलिए जब उज्ज्वला की ज्वाला ठंडी पड़ गयी तो अब साल में दो सिलेंडर फ्री का वादा आ गया है।

राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने के लिए नकदी की घोषणा कर रहे हैं क्योंकि तीन राज्यों के चुनाव में इन स्कीमों का लाभ सत्तारूढ़ दलों को मिला है। महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्त बनाने के लिए मूलभूत कार्यों के आधारभूत ढांचा विकसित करने के बजाय रुपए की रेवड़ियां बांटकर उनका बोट लेने की जुगत लगा रहे हैं। देखना है कि राजनीतिक दलों के चुनावी पिटारे के बहकावे में किसके बाद पर महिलाएं भरोसा करती हैं।

अधिक फसल सुनहरे कल की उम्मीदों पर पानी फेर रही

झारखंड का लातेहार जिलों के बालूमाथ व बारियातू के इलाके दो किस्म के टमाटर की खेती के लिए मशहूर हैं- एक है मोटे छिलके वाला गुलशन, जिसका इस्तेमाल सब्जी और विशेष तौर पर सलाद के रूप में किया जाता है। वहीं सलेक्शन नामक किस्म के टमाटर के छिलके की परत नरम होती है इसका इस्तेमाल सिर्फ सब्जी, चटनी और टोमैटो कैचअप के लिए किया जाता है। कुछ साल पहले तक टमाटर की लाली यहाँ के किसानों के गालों पर भी लाली लाती थी, लेकिन इस साल हालत यह हैं कि फसल तो बम्पर हुई लेकिन लागत तो दूर , तोड़ कर मंडी तक ले जाने की कीमत नहीं निकल रही। रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदग्गा में जिन किसानों ने टमाटर उगाए या फिर पत्ता या फूल गोभी या फिर पालक झ ट्रेक्टर से रौंद कर खड़ी फसल खुद ही चौपट कर रहे हैं। गोभी के दाम दो से चार रुपये तो टमाटर के दो रुपये। इतने में तुड़ाई भी निकलती, फिर मंडी तक कौन ले जाए। उत्तर प्रदेश के सौनभद्र जिले के हरवाई गाँव में सुर्ख लाल टमाटर की फसल पर रोटवेलर चला कर गेंहू बोए जा रहे हैं। यहाँ किसानों ने 15 हजार रुपये बीघा पर खेत किराये पर लिए, फिर टमाटर बोए। पिछले महीने तो 400 रुपए कैरेट (25 किलो) एक बार बिका फिर दाम 60 से 100 रुपये कैरेट गिर गए। अब 30 रुपये क्रेट तुड़ाई, 15 रुपये मंडी के पल्लेदार को, फिर परिवहन - आखिर किसान कितना घाटा सहे ! मध्य प्रदेश के बड़वानी में टमाटर मवेशी खा रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास भले ही बाजार में टमाटर के दाम 40 रुपए किलो हों, लेकिन टमाटर उगाने के लिए मशहूर देश के विभिन्न जिलों में टमाटर कूड़े में पडा है। छत्तीसगढ़ के टमाटर किसान तो जलवायु परिवर्तन की अजब मार झेल रहे हैं और उन्हें फसल खेत में नष्ट करनी पड़ रही हैं। दुर्ग जिले में पहले तो चक्रवती तूफान के चलते कोई 15 दिन बदली हुई फिर अचानक जाड़ा बढ़ गया। इससे टमाटर तेजी से पकने लगे। जब पके टमाटर की आवक ज्यादा हुई तो दाम गिर गए। यहाँ प्रायः इतनी ठंड पड़ती नहीं। अब टमाटर समय से पहले पक रहे हैं, न तोदो तो खुद गिर जाते हैं। मजबूर किसान फसल नष्ट कर रहा हैं। करीबी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हालात भी अलग नहीं हैं। यहाँ मेडक के शिवमपेट में टमाटर की तैयार फसल को आग लगाने की सैंकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। विदित हो टमाटर 15-27डिग्री के बीच के तापमान में सबसे अच्छे से उगते हैं, तथा इसके लिए माकूल औसत मासिक तापमान 21-23डिग्री होता है। 32डिग्री से अधिक तापमान फल लगने और उसके विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दक्षिणी राज्यों में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित टमाटर की खेती में सफेद फंगस और पट्टी में छेद करने वाले कीट की दिक्कत ने पहले से ही कीटनाशक का खर्च बढ़ाया था। फसल अच्छी हो गई तो बाजार में दाम नहीं मिलने से किसान कर्जे में दब गया। हालांकि न तो यह पहली बार हो रहा है और न ही केवल टमाटर के साथ हो रहा है। उम्मीद से अधिक हुई फसल सुनहरे कल की उम्मीदों पर पानी फेर देती है- घर की नई छप्पर, बहन की शादी, माता-पिता की तीर्थ-यात्रा; ना जाने ऐसे कितने ही सपने वे किसान सड़क पर ह्य केश क्रॉप ह्ल कहलाने वाली फसल के साथ फैंक आते हैं। साथ होती है तो केवल एक चिंताझ्र खेती के लिए बीज,खाद के लिए लिए गए कर्जे को कैसे उतारा जाए?

पूरे देश की खेती-किसानी अनियोजित ,शोषण की शिकार व किसान विरोधी है। तभी हर साल देश के कई हिस्सों में अफरात फसल को सड़क पर फैंकने और कुछ ही महीनों बाद उसी फसल की त्राहि-त्राहि होने की घटनाएं होती रहती हैं। किसान मेहनत कर सकता है, अच्छी फसल दे सकता है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को भी उसके परिश्रम के माकूल दाम , अधिक माल के सुरक्षित भंडारण के बारे में सोचना चाहिए। हर दूसरे-तीसरे साल कर्नाटक के कई जिलों के किसान अपने तीखे स्वाद के लिए मशहूर हरी मिर्चों को सड़क पर लावारिस फैंक कर अपनी हताशा का प्रदर्शन करते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में कभी टमाटर तो कभी अंगूर, कभी मूंगफली तो कभी गोभी किसानों को ऐसे ही हताश करती है। दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आए साल आलू की टनों फसल बगैर उखाड़े, मवेशियों को चराने की घटनाएं सुनाई देती हैं। आश्चर्य इस बात का होता है कि जब हताश किसान अपने ही हाथों अपनी मेहनत को चौपट करता होता है, ऐसे में गाजियाबाद, नोएडा, या दिल्ली में आलू के दाम पहले की ही तरह तने दिखते हैं।

कोचिंग संस्थान की भूमिका विवादों में रही

पिछले कुछ समय से देश भर में परीक्षाओं को लेकर शिक्षा क्षेत्र में खासकर छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच बेचैनी देखी जा रही है छात्र बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। इनका एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि परीक्षाओं के संचालन, पेपर-लीक या अन्य किसी भी वजह से उन्हें रद्द कर दिए जाने से छात्रों का खर्च तो बढ़ जाता ही है, केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, और यह आर्थिक चपत किसी न किसी रूप में देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, और देश के करदाताओं को ही उनकी भरपाई करनी होती है।

इन परीक्षाओं के लिए दृढ़ समर्पण, वर्षों की कड़ी मेहनत और व्यापक तैयारी की आवश्यकता होती है, और उसके बाद परीक्षा के पैटर्न में बदलाव, आयु या योग्यता मानदंडों में अकस्मात परिवर्तन, परीक्षाओं के संचालन में देरी या रद्द कर दिए जाने से छात्रों और उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों की आर्थिक से लेकर अन्य विभिन्न प्रकार की परेशानियां काफी बढ़ जाती हैं।

हाल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2024 पुनर्परीक्षा के परिणामों की घोषणा की जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा परिदृश्य के उल्लेखनीय घटनाक्रम को चिन्हित करता है। 23 जून, 2024 को संचालित इस पुनर्परीक्षा की आवश्यकता दो महत्त्वपूर्ण कारणों-पहले। की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए जाने और पेपर-लीक' के आरोपों की वजह-से पड़ी।

परीक्षा फिर से कराने का दबाव एनटीए पर 13 जून, 2024 को जारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण पड़ा। फिर से परीक्षा कराने और फिर उसका परिणाम प्रकाशित करने को लेकर एनटीए की त्वरित कार्रवाई मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धातों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। पर इसक्रे साथ-साथ इंजीनियरिंग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों की कई प्रकार प्रशासनिक सेवाओं जैसी इन राष्ट्रीय स्टार की परीक्षाओं के संचालन के आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें परीक्षाओं के केंटो की स्थापना और उनके ढांचे सबंधित कर्मचारीयों के वेतन मैटिरियल का प्रकाशन और वितरण प्रशासनिक व्यय आदि पर बड़ी राशि खर्च होती है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार, पूरे देश भर में संचालित की जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग (युपीएससी) की परीक्षाओं के संचालन पर लगभग 100 करोड, जीईई के संचालन पर 150 करोड, एनईईटी-नेट के संचालन पर 200 करोड़, सीटीईटी पर 120 करोड़ और युजीसी-नेट की परीक्षाओं के संचालन पर 80 करोड़ रुपए का खर्च आता है। पुनर्परीक्षा की स्थिति में इनमें और अधिक खर्च जुड़ जाता है। विडंबना यह है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर ही परेशानियां नहीं हैं। बिहार की बीपीएससी परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन और अराजकता से पहले उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस की रिव्यू ऑफिसर (आरओ/एआरओ) परीक्षा में प्रश्न पत्र के लीक को लेकर भी हंगामा हुआ था। उत्तरप्रदेश में ही सरकार को फरवरी में 60 हजार पुलिस कांस्टेबल की नियुक्त को ऐसे ही स्कैंडल के कारण रद्द करना पड़ा था। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी परीक्षाओं को लेकर बड़े विवाद नजरों में आते रहे हैं। विभिन्न परीक्ष-ाओं में होने वाले कदाचारों में कई बार देश के भीतर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है जैसा कि नेट की परीक्षा के दौरान गुजरात के गोधरा स्थित एक कोचिंग संस्थान की भूमिका विवादों में रही।

सवाल उठता है कि आखिर, देश की इतनी महत्त्वपूर्ण परीक्षाओं के संचालन में निष्पक्षता बनाए रखने और इनसे संबंधित आर्थिक चुनौतियों से निपटने का तरीका क्या हो? इन परीक्षाओं से देश के करोड़ों कर्णधारों का भविष्य तो दांव पर है ही, देश के स्वास्थ्य देखभाल और इंजीनियरिंग जैसे महत्त्वपूर्ण सेक्टरों में देश की श्रम शक्ति की गुणवत्ता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ. है। इस बाबत कदम उठाते हुए केद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 फरवरी, 2024 में राज्य सभा और लोक सभा, दोनों सदनों से पारित हो गया और 12 फरवरी, 2024 को इसने कानून की शक्ल भी अख्क्तियार कर ली। इसमें यूपीएससी, एस-ाएससी, रेलवे, बैकिंग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए आदि में कदाचार रोकने क बात कही गई है। चीटिंग यानी नकल को रोकने के लिए न्यूनतम तीन से पांच वर्षो तक के लिए कैद और नकल से संबंधित संगठित अपराध से जुड़े लोगों के लिए पांच से 10 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपये के आर्थिक दंड के प्रावधान भी हैं। इन परीक्षाओं के संचालन खासकर पिर से कराने की सूरत में आने वाले भारी आर्थिक नुकसान से बचने के लिए मजबूत प्रणाली बनाने और प्रक्रियाओं को लागू करने की जरूरत है ताकि न्यूनतम गलतियों और विवादों की नौबत आए। आर्थिक नुक-सान में इनके संचालन पर आने वाला खर्च ही शामिल नहीं होता, बल्कि इनमें लगने वाला अतिरिक्त समय और छात्रों, शिक्षकों और संचालकों का प्रयास, भी शामिल होता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव शैक्षणिक कैलेंडर और कॅरिअर की योजनाओं पर भी पड़ता है। जाहिर है कि इसके लिए परीक्षा से जुड़े प्राधिकारियों और नीति निमार्ताओं को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। इनमें परीक्षा संचालन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों में निवेश, लीक रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने जैसे कदमों की आवश्यकता हैं।

परीक्षा के दौरान तकनीकी खामियां गंभीर समस्या

परीक्षा प्रणाली किसी भी समाज में योग्यता और न्याय का प्रतीक होती है। न केवल व्यक्तिगत परीक्षा सफलता और अवसरों का निर्धारण करती है, बल्कि समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी सुदृढ़ करती है, लेकिन जब इस प्रणाली में प्रश्न- पत्र- लीक, तकनीकी खामियां और प्रशासनिक असफलताएं जैसे दोष आ जाते हैं, तो न केवल छात्रों के भविष्य को नुक-सान पहुंचता है, बल्कि शिक्षा प्रणाली में विश्वास भी कमजोर होता है। समस्याएं परीक्षा प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और नैतिक गिरावट की प्रतीक भी बन जाती हैं। इन खामियों को दूर करना समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है, जहां तकनीकी सुधारों के साथ-साथ प्रशासनिक पारदर्शिता और नैतिकता पर भी बल प्रदान किया जाए। परीक्षा प्रक्रिया में ब्लॉकचेन, एआई जैसी तकनीकों का उपयोग, पुनर्मुल्यांकन प्रणाली का अधिक पारदर्शी बनाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाना इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकते हैं लेकिन इसके साथ ही समाज में शिक्षा और योग्यता के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा देना भी उतना ही आवश्यक है। जब तक संबंधित पक्ष-छात्र, शिक्षक, प्रशासक, और समाज-इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तब तक यह प्रणाली अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी परीक्षा, प्रणाली ही समाज में योग्यता, समानता और प्रगति की बढ़ावा दे सकती है। भारत की वर्तमान परीक्षा प्रणाली और उसकी खामियों को समझना न केवल छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में योग्यता, निष्पक्षता और समानता की रक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाएं यह भी तय करती हैं कि कौन समाज जिम्मेदारियां संभालने योग्य हैं।

जब इस प्रणाली में चुकें और खामियां सामने आती हैं, तो ये प्रशासनिक समस्या ही नहीं होतीं, बल्कि हमारे समग्र सामाजिक-नैतिक ढांचे की कमजोरी को भी उजागर करती है। प्रश्न-पत्र - लीक की घटनाएं तंत्र की असफलताओं का स्पष्ट प्रमाण हैं। इनसे साफ होता है कि न केवल परीक्षा आयोजन में सुरक्षा का अभाव है, बल्कि इसमें शामिल लोगों को नैतिकता और कर्त्तव्यनिष्ठा भी संदिग्ध हैं। प्रश्न-पत्र-ली की घटनाएं छात्रों का विश्वास हिला कर रख देती है। उन पर मानसिक और भावनात्मक दबाव डालती है, जो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है।

तकनीकी खामियां विशेषकर ऑनलाइन परीक्षाओं में आज की डिजिटल दुनिया में बड़ी चुनौती बन गई हैं। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को समय और संसाधन बचाने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। लेकिन जब तकनीकी खामियां बार-बार सामने आती हैं, तो प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सर्वर डाउन होना, प्रश्नों का सही से लोड न होना या परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याएं दशार्ता है कि इस प्रणाली को अपनाने से पहले पूरी तैयारी और निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई।

इन खामियों से छात्रों का समय और आत्मविश्वास, दोनों प्रभावित होते हैं। तकनीकी खामियां प्रशासनिक अक्षमता की परिणाम भर नहीं है, बल्कि गहरे वैचारिक संकट का भी हिस्सा हैं तकनीकी खामियां दूर नहीं की जातीं तो तकनीक के प्रति अविश्वास पैदा होता है. और डिजिटल क्रांति का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। सही व्यवस्था छिन जाने से समाज में हताशा और आक्रोश पैदा होता है, जो स्थायी असंतोष का कारण बन सकता है। परीक्षा में पारदर्शिता को पुनर्स्थापित करना होगा। पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के अभाव से छात्रों के मन वहम घर कर जाता है कि उनकी मेहनत का मूल्यांकन सही से नहीं हो रहा है।

यह स्थिति विशेष रूप से उन-छात्रों के लिए घातक होती है जो सीमित संसाधनों के बावजूद कठिन प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। परीक्षा की समय-सारिणी में देरी और परिणाम आने में विलंब छात्रों के लिए अत्यधिक तनाव का कारण बनते हैं। यह समस्या विशेष रूप से उन छात्रों के लिए गंभीर होती है, जिनकी आयु सीमा समाप्त हो रही होती है, या जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं इससे वे अनिश्चितता की स्थिति में फंस जाते हैं। नकल और सेंधमारी की घटनाएं परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। नकल संगठित रूप से होती है, और परीक्षा केंद्रो पर निगरानी तंत्र विफल रहता है, तो सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार और मेहनती छात्रों को होता है। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान जैसे ब्लॉकचेन और एआई का उपयोग, प्रश्न-पत्र डिजिटल एन्क्रिप्शन, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, सख्त निगरानी तंत्र, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इससे निष्पक्षता और योग्यता को बढ़ावा मिलेगा।

युवाओं के प्रेरणास्रोत: स्वामी विवेकानंद

वर्तमान परिवेश में समाज में चारों तरफ अपराधों तथा भ्रष्टाचार का जो मकड़जाल फैल चुका है, वह घुन बनकर न सिर्फ देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है बल्कि युवा वर्ग भी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के इस दूषित माहौल में हताश व निराश है। ऐसे में युवा वर्ग सही मार्ग से न भटके, इसके लिए युवा शक्ति को जागृत कर उसे देश के प्रति कर्त्तव्यों का बोध कराते हुए सही दिशा में प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना और उचित मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है, जो प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि देश की आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ बलिदान कर लोगों में क्रांति का बीजारोपण करने वाले अधिकांश युवा ही थे। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरू इत्यादि देश के अनेक युवाओं ने देश की आन-बान और शान के लिए अपने निजी जीवन के समस्त सुखों का त्याग कर दिया था और अपना समस्त जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया था लेकिन आधुनिक युग में हम स्वार्थी बनकर ऐसे क्रांतिकारी युवाओं की जीवन गाथाओं को भूल रहे हैं और हम सब धीरे-धीरे भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे ही क्रांतिकारी युवा महापुरूषों की जीवन गाथाओं के जरिये देश की युवा पीढ़ी को समाज में व्याप्त गंदगी से बचाकर देश के विकास में उसका सदुपयोग किया जा सके, इसी उद्देश्य से आधुनिक भारत के महान चिंतक, दार्शनिक, समाज सुधारक, युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को ही प्रतिवर्ष ह्यराष्ट्रीय युवा दिवसह्ल के रूप में मनाया जाता है, जो बहुत कम आयु में अपने विचारों के चलते समस्त जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सफल हुए थे।

स्वामी विवेकानंद के वक्तव्यों का आम जनमानस और खासकर युवाओं के मनोमस्तिष्क पर कितना प्रभाव पड़ता था, इसका उनके शिकागो भाषण से बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता। 11 सितम्बर 1893 को जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिन्दू धर्म पर अपने प्रेरणात्मक भाषण की शुरूआत उन्होंने ह्यमेरे अमेरिकी भाइयों और बहनोंह्ल के साथ की थी तो बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही थी। अपने उस भाषण के जरिये उन्होंने दुनियाभर में भारतीय अध्यात्म का ड-ंका बजाया था। विदेशी मीडिया और वक्ताओं द्वारा भी स्वामीजी को धर्म संसद में सबसे महान व्यक्तित्व और ईश्वरीय शक्ति प्राप्त सबसे लोकप्रिय वक्ता बताया जाता रहा। यह स्वामी विवेकानंद का अद्भुत व्यक्तित्व ही था कि वे यदि मंच से गुजरते भी थे तो तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती थी। उन्होंने 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन तथा 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। 4 जुलाई 1902 को इसी रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण किए वे चिरनिद्रा में लीन हो गए।

स्वामी विवेकानंद सही मायनों में युवाओं के प्रेरणास्रोत और आदर्श व्यक्ति्व के धनी थे, जिन्हें उनके ओजस्वी विचारों और आदर्शों के कारण ही जाना जाता है। विवेकानंद सदैव कहा करते थे कि उनकी आशाएं देश के युवा वर्ग पर ही टिकी हुई हैं। वे आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि थे और खासकर भारतीय युवाओं के लिए उनसे बढ़कर भारतीय नवजागरण का अग्रदूत अन्य कोई नेता नहीं हो सकता। अपने 39 वर्ष के छोटे से जीवनकाल में स्वामी जी अलौकिक विचारों की ऐसी बेशकीमती पूंजी सौंप गए, जो आने वाली अनेक शताब्दियों तक समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेगी। उनका कहना था कि मेरी भविष्य की आशाएं युव-ाओं के चरित्र, बुद्धिमत्ता, दूसरों की सेवा के लिए सभी का त्याग और आज्ञाकारिता, खुद को और बड़े पैमाने पर देश के लिए अच्छा करने वालों पर निर्भर है। उन्होंने देश को सुदृढ़ बनाने और विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए हमेशा युवा शक्ति पर भरोसा किया। उनका कहना था कि मेरी भविष्य की आशाएं युवाओं के चरित्र, बुद्धिमत्ता, दूसरों की सेवा के लिए सभी का त्याग और आज्ञाकारिता, खुद को और बड़े पैमाने पर देश के लिए अच्छा करने वालों पर निर्भर है। युवा शक्ति का आव्हान करते हुए उन्होंने अनेक मूलमंत्र दिए।

घूँघट की बगावत

19 जनवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

ईश्वर और ज्ञान की खोज में स्वामी विवेकानंद ने समर्पित कर दिया था अपना पूरा जीवन

जन्म और परिवार- कोलकाता में 12 मई को 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद की मां धार्मिक स्वभाव की महिला थीं और उनकी पूजा-पाठ में गहरी रुचि थी। जिसकी वजह से नरेंद्र नाथ बचपन से ही अपनी मां के धार्मिक आचरण और नैतिकता से प्रभावित थे। यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में सांसारिक मोह माया को त्याग दिया था और संन्यासी मार्ग अपना लिया था। स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है।

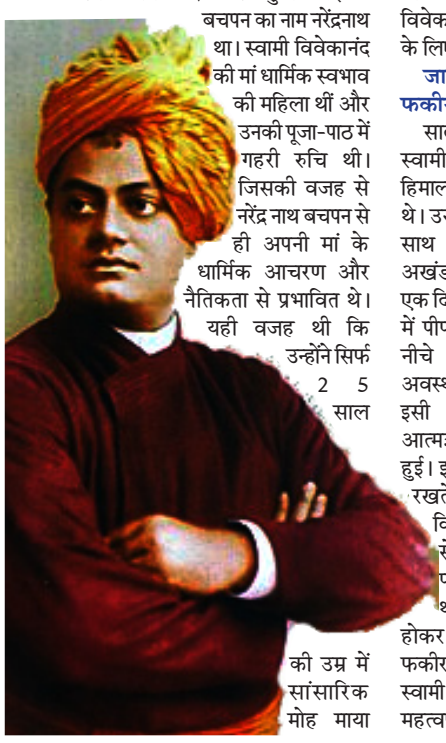

जान बचाने वाले फकीर की कहानी

साल 1890 में स्वामी विवेकानंद हिमालय यात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके साथ स्वामी अखंडानंद भी थे। एक दिन काकड़ीघाट में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे, इसी दौरान उनको आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। इस यात्रा को जारी रखते हुए स्वामी विवेकानंद जब अल्मोड़ा से करबला कब्रिस्तान के पास पहुंचे, तो भूख और थकान की वजह से वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। तब उनको एक फकीर ने खीरा खिलाया। जिससे वह होश में आए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की यह घटना उनके लिए महत्वपूर्ण और प्रेरक कहानी बन गई।

स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि उनका पूरा जीवन प्रेरणा का अद्भुत स्त्रोत है। स्वामी विवेकानंद ने सांसारिक मोह माया को छोड़कर ईश्वर और ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। बता दें कि स्वामी विवेकानंद को गुरु रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आइए जानते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

ऐतिहासिक भाषण- 11 दिसंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह क्षण भारत के लिए गर्व और ऐतिहासिक का पल था। अपने भाषण की शुरूआत स्वामी विवेकानंद ने 'अमेरिका के भाइयों और बहनों' कहकर की थी। उनके इस शब्द ने पूरे सभागार को भावनाओं से भर दिया था। स्वामी विवेकानंद के संबोधन से सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। जोकि पूरे दो मिनट तक जारी रही।

मृत्यु- बता दें कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 04 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए हुई थी। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों का मानना है कि उन्होंने महासमाधि में प्रवेश कर लिया था। लेकिन उनकी मृत्यु का संभावित कारण मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के फटने को बताया गया था। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद को अनुमान था कि वह 40 साल तक जीवित नहीं रहेंगे।

दमदार अभिनय के बावजूद कहानी कई हिस्सों में बोझिल मूवी आजाद

आजाद आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई है। आजाद के साथ, दो स्टार किड्स बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं: एक हैं रवीना टंडन की बेटी, राशा थडानी, और दूसरे हैं अजय देवगन के भतीजे, अमन देवगन। अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन, डायना पेंटी, पीयूष मिश्रा और टीवी अभिनेता मोहित मलिक भी हैं। आजाद फिल्म में इनमें से किसी भी अभिनेता का नाम नहीं है, बल्कि यह अजय देवगन के किरदार का घोड़ा है। फिल्म की पूरी कहानी इसी घोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है। अभिनय, निर्देशन और अन्य बातों के संदर्भ में नीचे फिल्म की विस्तृत समीक्षा प्राप्त करें।

कहानी

फिल्म की कहानी स्वतंत्रता-पूर्व युग की है, जहाँ गोविंद नाम का एक लापरवाह गाँव का लड़का है। गाँवों पर जमींदारों का कब्जा है, और इन जमींदारों में से एक की एक खूबसूरत बेटी है जिसका नाम जानकी है। वह अपनी बेटी की शादी अंग्रेज कमिंग के बेटे से करना चाहता है, जिसके चलते वह अंग्रेजों की हर मांग पूरी कर रहा है। वह अंग्रेजों के लिए गांवों को खाली कराकर उन पर कब्जा भी कर रहा है। इतना ही नहीं, जो ग्रामीण कर नहीं चुका पा रहे हैं, उन्हें अंग्रेजों के बंदी बनाकर दक्षिण अफ्रीका भेजा जा रहा है।

इसके अलावा फिल्म में एक मसीहा भी है, विक्रम ठाकुर। आजाद में दो प्रेम कहानियां हैं, एक विक्रम ठाकुर की और दूसरी गोविंद की, जो अलग-अलग समय पर सेट हैं। विक्रम ठाकुर की मौत के बाद फिल्म में चीजें बदल जाती हैं। यह घटना गोविंद को बदल देती है। कहानी एक दिलचस्प दौड़ के साथ खत्म होती है, जिसे जीतकर गोविंद न सिर्फ अपने गांव का हीरो बन जाता है, बल्कि गांव वालों को करों से भी मुक्त कर देता है।

अमन देवगन ने अपनी पहली फिल्म के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत की है, जैसे घुड़सवारी, डांसिंग और बहुत कुछ। राशा थडन भी अपने लुक से प्रभावित करती हैं, हालांकि, फिल्म में उनका कुल स्क्रीन टाइम काफी सीमित है। एकमात्र कमजोर पहलू उनके और अमन देवगन के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री है। इस बीच, दोनों नवोदित कलाकारों ने अपने उच्चारण पर काफी मेहनत की है, जो फिल्म में साफ झलकता है। अजय देवगन का किरदार आपको 'दिलजले' में उनके किरदार की याद दिलाएगा। उनकी मौत फिल्म का सबसे अहम और भावनात्मक मोड़ है।

डायना पेंटी ने ईमानदारी से अभिनय किया है, लेकिन उनके किरदार में दम नहीं है। जहां मोहित मलिक ने निगेटिव रोल में कमाल दिखाया है, वहीं पीयूष मिश्रा का काम फिल्म में ठीक-ठाक रहा। निर्देशन अभिषेक कपूर ने फिल्म का निर्देशन और लेखन दोनों ही किया है। फिल्म को बड़े पर्दे पर अच्छे से पेश किया गया है, लेकिन कहानी घिसी-पिटी है। एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की वही कहानी, अमीरों का अत्याचार और एक अन्यायी पिता जो अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर रहा है।

दमदार अभिनय के बावजूद कहानी कई हिस्सों में बोझिल हो जाती है। फिल्म की लंबाई कम की जा सकती थी, जो फिलहाल 2 घंटे 27 मिनट है। निर्देशन कुछ जगहों पर तारीफ के काबिल है, इमोशनल सीन काफी शानदार हैं।

कुल मिलाकर 'आजाद' की शुरूआत कमजोर है और कहानी में नए लोगों को स्थापित करने में फिल्म को काफी समय लगता है। कमजोर स्क्रिप्ट और रोमांटिक एंगल की कमी के कारण यह दर्शकों को आकर्षित करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाती। फिर भी फिल्म में दमदार अभिनय को मौका दिया जा सकता है।

नील गैमन पर कई महिलाओं ने यौन दुराचार के लगाए आरोप

न्यूयॉर्क मैगजीन के लेख में, गैमन और उनकी पूर्व पत्नी अमांडा पामर की पूर्व नैनी स्कारलेट पावलोविच उन महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने लेखक पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

द सैंडमैन और कोरलीन जैसी रचनाओं के लिए मशहूर ब्रिटिश लेखक नील गैमन पर कई महिलाओं ने यौन दुराचार के आरोप लगाए हैं। न्यूयॉर्क मैगजीन के एक नए लेख 'देयर इज नो सेफ वर्ड' में आठ महिलाओं ने अपने परेशान करने वाले अनुभव साझा किए हैं। ये लेख 2023 की शुरूआत में सामने आए पिछले आरोपों का विस्तार करते हैं, जिन्हें पहली बार पॉडकास्ट सीरीज 'मास्टर: द एलेगेशन्स अगेंस्ट नील गैमन' में खोजा गया था। गैमन ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी यौन संबंध सहमति से बने थे।

न्यूयॉर्क मैगजीन के लेख में, गैमन और उनकी पूर्व पत्नी अमांडा पामर की पूर्व नैनी स्कारलेट पावलोविच उन महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने लेखक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पावलोविच ने एक घटना का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि जब वह गैमन के घर पर नहा रही थी, तब लेखक उनके पास आया और उन्हें अपनी गोद में बैठने को कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

पावलोविच ने आगे खुलासा किया कि गैमन ने उन्हें कई बार यौन संबंध बनाने पर मजबूर किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन सब के लिए उनकी सहमति नहीं थी। एक अन्य परेशान करने वाले घटना के बारे में बताते हुए पावलोविच ने कहा कि गैमन ने उन्हें इतनी हिंसक तरीके से ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया कि उन्हें उल्टी हो गयी। इतना ही नहीं नैनी ने दावा किया कि इसके बाद गैमन ने उन्हें इस उल्टी को खाने के लिए भी मजबूर किया।

इन आरोपों के जवाब में, गैमन के प्रतिनिधियों ने एक साक्षात्कार के दौरान मीडियाकर्मियों को बताया कि आरोप 'झूठे हैं, निंदनीय तो हैं ही'। दावों के बावजूद, पावलोविच गैमन के संपर्क में रही और उसे आश्वस्त भी किया कि उनकी बातचीत सहमति से हुई थी। हालांकि, बाद में उसने जनवरी 2023 में गैमन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई, हालांकि यह मामला अंततः बंद कर दिया गया था। न्यूयॉर्क मैगजीन के लेख में आगे आई एक अन्य महिला कैरोलीन वॉलनर ने गैमन के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के ऐसे ही अनुभव साझा किए। वॉलनर ने न्यूयॉर्क के वुडस्टॉक में गैमन की संपत्ति पर एक केयरटेकर के रूप में काम किया था, और एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया, जहां यौन संबंध लेन-देन बन गए, जो उसके रहने की व्यवस्था से जुड़े थे। वॉलनर के अनुसार, गैमन का व्यवहार उस समय सीमा पार कर गया, जब काम के एक लंबे दिन के बाद, उसने कथित तौर पर अपने बच्चे के पास पहुंचकर, जो बिस्तर पर था, उसका हाथ अपने लिंग पर रख दिया। उसने इस मुठभेड़ को ₹गलतह बताया और महसूस किया कि गैमन बुनियादी सीमाओं का सम्मान नहीं करता था।

▶ जयदीप अहलावत का शो जोखिमों से भरा है

हत्याकांड सुलझाने जमुनापार से सीधे पूर्वोत्तर पहुंचे हाथी राम चौधरी

लगभग पाँच साल हो गए हैं जब से दर्शकों का एक समूह अपने घरों में बंद (लॉकडाउन) होकर पाताल लोक और जयदीप अहलावत की प्रतिभा से परिचित हुआ था। यह वह समय था जब ओटीटी शो में अधिक जोश और तेज हुआ करता था। पाताल लोक सीजन 2 में निमार्ता (निमार्ता सुदीप शर्मा और निर्देशक अविनाश अरुण) कुछ संयम दिखाते दिख रहे हैं, और बहुत सारे खून-खराबे को सावधानी से कम किया गया है। शॉक वैल्यू अभी भी बनी हुई है, जिसमें पहले कुछ मिनटों में एक कटे हुए, बिना सिर वाले शरीर का बहुत विस्तृत दृश्य आपका स्वागत करता है। यह कहना सुरक्षित है कि पाताल लोक 2 का पहले भाग से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि इंस्पेक्टर हाथी राम चौधरी (जयदीप अहलावत), ऑफिसर अंसारी (इशवाक सिंह), एसएचओ विर्क (अनुराग अरोड़ा) और हाथी राम के परिवार के सदस्य - उनकी पत्नी (गुल पनांग द्वारा अभिनीत) और बेटे सिद्धार्थ (बोधिसत्व शर्मा) जैसे कुछ किरदार हैं। हाथी राम और अंसारी के रास्ते भले ही सफल आईपीएस बनने के बाद अलग हो गए हों, लेकिन हाई-प्रोफाइल जोनाथन थॉम की हत्या के बाद उनके रास्ते एक-दूसरे से मिल जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लगभग पूरे नागालैंड का समर्थन प्राप्त है। अंसारी को प्रभारी बनाया जाता है। इस बीच, जमुनापार पुलिस स्टेशन का हाथी राम एक निश्चित राहुल पासवान की तलाश कर रहा है, जो एक बैंड-बाजा वाला लड़का है, जिसका पता नहीं चल पा रहा है। अप्रत्याशित रूप से, ये दोनों मामले जुड़ते हैं, और एपिसोड तीन तक, हाथी राम-अंसारी की जोड़ी नागालैंड में पहुँच जाती है, इस बार अंसारी प्रभारी होता है।

ओजी सीजन की तरह, हत्याएँ होती रहती हैं और लोग ऐसे मरते हैं जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और समस्याएँ और भी उलझ जाती हैं, इससे पहले कि हाथी राम अपनी हाथी जैसी याददाश्त के साथ आखिरकार रहस्य को एक-एक करके सुलझाए।

अगर आपको पहला सीजन पसंद आया है और आपने इसे धार्मिक रूप से देखा है, तो आपको पता होगा कि कहानी का अंत कैसा होगा - धरती लोक के लोगों के लिए स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच की रेखाएँ हमेशा धुंधली रहेंगी। अगर पहले सीजन में हिंदी पट्टी में वर्ग विभाजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो दूसरे सीजन में नागालैंड की ओर एक्शन दिखाया गया है - जहाँ एक पाताल लोक है, जो अपराध और लालच में समान रूप से डूबा हुआ है।

हालांकि, ऐसा लगता है कि पहले सीजन की निर्दयता, कच्चापन और धैर्य गायब है। पहले सीजन में, कथा बहुत करीब से टकराती है। दर्शकों को उस पाताल लोक के सामने लाया गया, जिसके बारे में वे जानते हैं, लेकिन अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस सीरीज ने हमें इस अहसास से झिझकने और असहज होने पर मजबूर कर दिया कि पाताल लोक का अंधकार हमारे आस-पास और हमारे भीतर मौजूद है। सीजन 2 घर के इतने करीब नहीं पहुँचता है, लेकिन यह कुछ ऐसा करता है जिसे मुख्यधारा में लंबे समय से अनदेखा किया गया है।

नागालैंड की पृष्ठभूमि में, एक शानदार अंदरूनी-बाहरी बहस को बारीकियों से पेश किया गया है और इसे विकसित होने के लिए जगह दी गई है। हाथी राम जैसे 'गांव के गँवार' के साथ अवधारणा की समझ के साथ, जिसे यह नहीं पता कि नागालैंड भारतीय मानचित्र पर कहाँ है, निर्माता यह सुनिश्चित करते हैं कि दर्शकों का हर सदस्य इस प्रतीत होता है कि एकदम सही सेटिंग में सामाजिक-राजनीतिक दरारों को समझ पाएगा।

एक दर्शक के रूप में, स्क्रीन पर एक पूर्वोत्तर राज्य को दिखाया जाना एक स्वागत योग्य बदलाव है। उड़ती गोलियों के बीच, आप हरे-भरे हरियाली और पहाड़ों से घिरे शांत परिवेश की झलक पाते हैं। इसके साथ ही उत्तर-पूर्वी कलाकार भी हैं जो प्रामाणिकता को बढ़ाते हैं - चाहे वह मेरेनला इमसोंग द्वारा निभाई गई भगोड़ी रोज लिजो हो या बेचैन रूबेन थॉम, जिसका जुनून एलसी शेखोस द्वारा पूर्णता के साथ सामने लाया गया है या केन के रूप में जाह्नु बरुआ, जो दिल्ली बिजनेस समिट में डील को पक्का करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

नागालैंड की पृष्ठभूमि में, एक शानदार अंदरूनी-बाहरी बहस को बारीकियों से पेश किया गया है और इसे विकसित होने के लिए जगह दी गई है। हाथी राम जैसे 'गांव के गँवार' के साथ अवधारणा की समझ के साथ, जिसे यह नहीं पता कि नागालैंड भारतीय मानचित्र पर कहाँ है, निर्माता यह सुनिश्चित करते हैं कि दर्शकों का हर सदस्य इस प्रतीत होता है कि एकदम सही सेटिंग में सामाजिक-राजनीतिक दरारों को समझ पाएगा।

जयदीप अहलावत ने पहले सीजन में खुद को सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया, और दूसरे सीजन में भी उन्होंने अपनी हमेशा की तरह ही शानदार अभिनय जारी रखा। हाथी राम के रूप में वे बेदाग हैं, और पांच साल पहले हमारे दिलों को जीतने वाले पुलिस अधिकारी के रूप में उन्हें फिर से देखना एक ट्रीट है।

इश्वाक सिंह अंसारी के रूप में बेहतरीन हैं। तिलोत्तमा शोम इस सीजन में शामिल हुई थीं, और उन्होंने एसपी मेघना बरुआ के रूप में बेदाग अभिनय किया, जो छह बच्चों की मां और एक दुर्जेय पुलिस अधिकारी हैं, जिन्हें पुरुष-प्रधान क्षेत्र में अपनी जगह बनानी है। उनका ट्रैक आपको और देखने की चाहत देता है। और फिर, कपिल रेड्डी के रूप में नागेश कुकुनूर हैं, जो अपने सीमित स्क्रीनटाइम में जादू बिखेरते हैं। पाताल लोक सीजन 2 पहले सीजन से काफी अलग है। हालांकि इसमें कई ऐसे तत्व नहीं हैं जो दर्शकों को पहले सीजन में पसंद आए थे, लेकिन यह उत्तर-पूर्व (खास तौर पर नागालैंड) से संबंधित कई संवेदनशील मुद्दों को और भी जटिल बनाता है। यह एक ऐसे क्षेत्र में साहसपूर्वक प्रवेश करता है, जहां कई लोग जाने से कतराते हैं। इस कारण से तथा अन्य अनेक कारणों से, यह फिल्म निश्चित रूप से देखने लायक है।

कम उम्र में ही विज्ञापनों में मॉडलिंग करने लगी थीं

अभिनेत्री मिनिषा लांबा का जन्म जाट परिवार में हुआ था। उनके बड़े होने पर पिता आतिथ्य व्यवसाय में थे और इसने लांबा को देश भर में यात्रा करने और कई लोगों से मिलने का अवसर दिया। वे कई भाषाओं जैसे पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच में बात कर सकती है।

बॉलीवुड की गुमनाम और प्रतिभाशाली अभिनेत्री मिनिषा लांबा का जन्म जाट परिवार में हुआ था। उनके बड़े होने पर पिता आतिथ्य व्यवसाय में थे और इसने लांबा को देश भर में यात्रा करने और कई लोगों से मिलने का अवसर दिया। वे कई भाषाओं जैसे पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच में बात कर सकती है। दिल्ली में डिग्री के लिए अध्ययन करते समय लांबा ने एक शौक के रूप में मॉडलिंग की और जल्द ही भारतीय मॉडलिंग उद्योग में एक अच्छी तरह से स्थापित मॉडल बन गई। उनके शुरूआती मॉडलिंग कार्य के उदाहरणों में एलजी, सोनी, सनसिल्क और अन्य जैसी कंपनियों के कई टेलीविजन विज्ञापन शामिल हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com